राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

स्वतंत्र प्रभात

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें........ 9511151254

@swatantraprabhatmedia | @swatantramedia | RNI.No. UHIN/2012/43078 (epaper.swatantraprabhat.com) | @SwatantraPrabhatonline | news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एंव अयोध्या, प्रयागराज, मिर्जापुर, गोरखपुर, बरेली, बुंदेलखंड, उत्तराखंड, देहरादून

सीतापुर, मंगलवार, 16 दिसंबर 2025

वर्ष 14, अंक 243, पृष्ठ 04, मूल्य: 01 रुपया

www.swatantraprabhat.com

गाज़ियाबाद, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, झारखण्ड, बिहार, मध्य प्रदेश, असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित

जीआरपी के जवानों ने बुजुर्ग की बचाई जान, रेलवे ट्रैक पर ट्रेन आने से पहले पटरी से हटाया..03

श्रीभूमि जिले के आर्दश कृष्णनगर गाँव विकास के लाभ से वंचित..04

नितिन नबीन... सिर्फ एक नाम नहीं, पीएम मोदी की खींची वो लकीर जो सियासत की तस्वीर बदल रही, नैरेटिव चेंज कर रही

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली- बिहार में कायस्थ जाति की आबादी महज 0.6 प्रतिशत है, फिर भी बीजेपी ने एक कायस्थ युवा नेता नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व सौंपा. यह कदम जातिगत समीकरणों से ऊपर उठकर एक मजबूत संदेश देता है. पीएम नरेंद्र मोदी का नजरिया हमेशा से यही रहा है- जाति की दीवारें तोड़कर योग्यता और समर्पण को प्राथमिकता देना. जानकारों की नजर में नितिन नबीन का उदय इसी सोच का प्रतीक है जो कास्ट पॉलिटिक्स के चक्रव्यूह में फंसी विपक्षी पार्टियों को चुनौती देता है. यह नियुक्ति सिर्फ एक प्रमोशन नहीं, बल्कि मोदी की खींची हुई वो लकीर है जो राजनीतिक नैरेटिव को हमेशा के लिए बदल सकती है-जहां वोट बैंक की बजाय बड़े विजन का सम्मान हो।

बिहार की जातिगत जनगणना

बिहार सरकार की हालिया जातिगत जनगणना रिपोर्ट के अनुसार, कायस्थ समुदाय की आबादी कुल 13 करोड़ की आबादी में महज 0.6 प्रतिशत है और आबादी में भागीदारी लगभग 7.8 लाख है. हालांकि, कई कायस्थ संगठन इस आंकड़े को भ्रामक बताते हैं. दूसरी ओर जानकार कहते हैं कि यह आंकड़ा सतह पर छोटा लगता है, लेकिन ऐतिहासिक संदर्भ में कायस्थों का प्रभाव हमेशा से असाधारण रहा है. वे प्रशासनिक और बौद्धिक क्षेत्रों में मजबूत पकड़ रखते हैं जो वोट बैंक से ज्यादा 'इन्फ्लुएंस बैंक' का काम करता है. बिहार में कायस्थों ने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आधुनिक राजनीति तक योगदान दिया है. नितिन नबीन का चयन इस प्रभाव को भी मान्यता देता है।

पीएम मोदी का स्पष्ट है नजरिया

पीएम मोदी का राजनीतिक विजन हमेशा से राष्ट्रीय एकता पर आधारित रहा है, जहां जाति को 'वोट डिवाइडर' की बजाय 'ब्रिज बिल्डर' बनाया जाए. आबादी कम भी हो लेकिन योग्यता ज्यादा तो जाति को बैलेंसिंग फैक्टर की बजाय मेरिट को पैमाना बनाना चाहिए. साफ तौर पर पीएम मोदी का यह कदम बिहार की जाति-केंद्रित उस राजनीति को चुनौती देता है जहां यादव (14.26%), कुशवाहा (4.21%) और भूमिहार (2.87%) जैसे समुदाय की आबादी को देखकर राजनीतिक दल अपनी रणनीतियां बनाते हैं. पीएम मोदी का यह कदम बताता है कि बीजेपी का 'सामाजिक न्याय' अंत्योदय के उत्थान के साथ ही योग्यता को सम्मान वाली नीति से भी जुड़ती है।

संख्या से ज्यादा रणनीतिक महत्व

भारत के प्रमुख राज्यों में कायस्थों की जनसंख्या सीमित तो है, लेकिन समुदाय बेहद रणनीतिक महत्व रखता है. बिहार में लगभग 0.6 प्रतिशत आबादी के साथ संख्या करीब 8 करोड़ कही जाती है. इसी तरह उत्तर प्रदेश में लगभग 24 करोड़ आबादी में कायस्थों की संख्या करीब 19.71 लाख है जो कुल 0.8 प्रतिशत है. लेकिन, इसके साथ ही तथ्य यह है कि खासकर लखनऊ और कानपुर जैसे शहरी क्षेत्रों में बेहद ही प्रभावशाली है. इसी प्रकार पश्चिम बंगाल की 10 करोड़ आबादी में यह 2.7 मिलियन यानी 2.7% , दिल्ली की 2 करोड़ जनसंख्या में कायस्थों का प्रतिशत 2-3% अनुमानित है. खास बात यह कि राष्ट्रीय राजधानी के ब्यूरोक्रेसी में इनकी मजबूत पकड़ है।

कास्ट कार्ड नहीं, काबिलियत का दांव

मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनसंख्या में करीब 5-6 लाख यानी 0.7% हिस्सेदारी है, महाराष्ट्र की 12 करोड़ आबादी में 2-3 लाख 0.2% आबादी और पंजाब की 3 करोड़ में महज 0.5% से कम अनुमानित है. वहीं, असम में 6.95 लाख जनसंख्या कही जाती है जो 2.2% है. ये आंकड़े बताते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर कुल जनसंख्या 3 से 4 करोड़ के बीच करीब 2 प्रतिशत अनुमानित है. स्पष्ट है कि कायस्थों का वोट बैंक बेहद छोटा है. अब सवाल यह कि आखिर इतनी कम आबादी वाले वर्ग पर भाजपा क्योंकर इतना बड़ा दांव लगा रही है. दरअसल, यही तो वो बात है जहां पीएम मोदी बड़ी लकीर खींचते हुए नजर आते हैं।

पीएम मोदी का संदेश साफ है!

दरअसल, कायस्थ आबादी का प्रभाव शहरी (Urban), शिक्षित (Educated) और प्रभावशाली (Influential) वर्ग में फैला है. कहा जाता है कि बुद्धिजीवियों की विरासत किसी वर्ग ने संभाल रखी है तो यही समुदाय है. जब कास्ट सेंसस जैसे मुद्दे उभर रहे हैं तो बीजेपी जाति को 'डिवाइडर' की बजाय 'यूनिफायर' बनाएगी. नितिन नबीन का चयन यूपी-बिहार गठजोड़ को मजबूत करता है जहां कायस्थ वोटर अन्य जातियों को प्रभावित कर सकते हैं. संख्या से परे सॉफ्ट पावर'कास्ट पॉलिटिक्स में कायस्थों का वोट बैंक 'हार्ड न्यूमर्स' से ज्यादा 'सॉफ्ट इन्फ्लुएंस' पर टिका है।

नितिन नबीन की एंट्री से बदला गेम

बिहार में 0.6% होने के बावजूद इस वर्ग के लोग सरकारी नौकरियों में अनुमानित 6.68% प्रतिनिधित्व रखते हैं जो उनकी शिक्षा, योग्यता और क्षमता का प्रमाण है. उत्तर प्रदेश में 0.8% आबादी वाले कायस्थ IAS/IPS में बहुत बड़ी पैठ रखते हैं. पश्चिम बंगाल में 2.7% कायस्थ वोटर ञ्जरूष्ट और BJP दोनों को आकर्षित करते हैं, जबकि दिल्ली में उनका अरबन मिडिल क्लास बेस मोदी की 'एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स' से सीधे तौर पर जुड़ता है. महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कम संख्या होने पर भी वे 'स्विंग वोटर्स' की भूमिका निभाते . पीएम मोदी का नजरिया यही है कि वोट बैंक को जाति से नहीं, बल्कि उनकी योग्यता से मापें. नितिन नबीन का उदय बताता है कि बीजेपी छोटे, मगर प्रभावी समुदायों को 'फेस' देती थी, देती है और देती रहेगी।

कास्ट पॉलिटिक्स के बीच मैसेज

भारतीय राजनीति जाति के चक्रव्यूह में फंसी हुई है. बिहार में RJD यादव-मुस्लिम पर, क्क में स्क्त यादव-मुस्लिम और W B में TMC बंगाली अस्मिता पर. ऐसे में नितिन नबीन का चयन एक तीर तीन निशान मारता है. पीएम मोदी का नजरिया 'सबका साथ' का रहा है, जो 2014 से 'जाति-मुक्त' राजनीति का दावा करता आया है. कायस्थों की कम आबादी चुनकर मोदी कह रहे हैं- हम संख्या नहीं, क्षमता देखते हैं. यह विपक्ष को भी एक प्रकार की चुनौती है जो जाति आधारित राजनीति पर अटका हुआ है, वहीं बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वह विकास, शासन और समावेशिता पर फोकस करेगी. भाजपा युवा मोर्चा से विधायक और बिहार सरकार में मंत्री के बाद अब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तक पहुंचने का नितिन नबीन का बैकग्राउंड पीएम मोदी की 'युवा ऊर्जा' वाली सोच को भी मूर्त रूप देता है।

मोदी की लकीर नैरेटिव बदल देगी!

दरअसल, नितिन नबीन सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि मोदी की रणनीतिक सोच का प्रतीक हैं, क्योंकि नितिन नबीन 'कास्ट से कास्टलेस पॉलिटिक्स' की ओर मूव करते मोदी की वो बड़ी लकीर हैं जो नैरेटिव बदलने की ताकत रखती है. 45 वर्ष के नितिन नबीन ने बिहार में पांच बार विधायक रहकर साबित किया कि मेहनत जाति से ऊपर है. उनकी नियुक्ति कास्ट पॉलिटिक्स को आईना दिखाती है. पीएम मोदी का संदेश यही है कि भारत की विविधता को एकजुट करो, विभाजन न फैलाओ. जानकार कह रहे हैं क विपक्ष अगर इसे समझे तो शायद अपनी रणनीति बदल ले; वरना पीएम मोदी की खींची इस बड़ी लकीर ने नया इतिहास तो रच ही दी है।

एक साल में 6-6 इन्क्रीमेंट दुलारे कर्मचारियों पर खूब मेहरबान थे CJI, अब सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

हर नौकरीपेशा इंसान को हर साल अपनी सैलरी बढ़ने की उम्मीद जरूर रहती है. प्राइवेट से लेकर सरकारी तक सभी दफ्तरों में सालाना वेतनवृद्धि एक सामान्य प्रक्रिया होती है. लेकिन क्या हो अगर किसी कर्मचारी की सालभर के अंदर छह-छह बार सैलरी बढ़ जाए. यह सुनकर आप हैरान हुए न... लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बीते कुछ वर्षों में ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली. यहां कई मुख्य न्यायाधीशों (CJI) ने रिटायरमेंट से ठीक पहले अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करते हुए कुछ चुनिंदा कर्मचारियों को एक नहीं, बल्कि दो से तीन और कुछ मामलों में छह तक अतिरिक्त वेतनवृद्धि मंजूर कर दी. जिन न्यायाधीशों का कार्यकाल छोटा रहा, उन्होंने भी सालाना इन्क्रीमेंट के अलावा अपने निजी स्टाफ या 'असाधारण कार्य' करने वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त इन्क्रीमेंट दिए. बीते चार वर्षों में ही सुप्रीम कोर्ट के करीब 2,000 कर्मचारियों को कम से कम दो से तीन अतिरिक्त वेतनवृद्धि मिली, जबकि कुछ 'खास' कर्मचारियों को छह अतिरिक्त इन्क्रीमेंट तक मिले. इसके चलते कुछ कर्मचारियों का वेतन सामान्य वेतन से करीब 150 प्रतिशत तक पहुंच गया।

बढ़ी हुई सैलरी पर क्या हुआ फैसला?

इस असमानता और विसंगति को दूर करने के लिए तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने सभी जजों की फुल कोर्ट बैठक बुलाई थी. इस बैठक में अधिकांश न्यायाधीशों की राय थी कि न तो सुप्रीम कोर्ट कोई 'साम्राज्य' है और न चीफ जस्टिस कोई 'राजा'... जो अपने विवेक से चुनिंदा लोगों को वेतन लाभ बांटें. लंबी चर्चा के बाद फुल कोर्ट ने फैसला किया कि इस तरह की विवेकाधीन वेतनवृद्धि की प्रथा को तत्काल समाप्त किया जाए. फुल कोर्ट ने यह भी तय किया कि बीते वर्षों में दी गई अतिरिक्त वेतनवृद्धि को वापस लिया जाएगा और भविष्य में अगर किसी विशेष इन्क्रीमेंट पर विचार होगा तो वह केवल फुल कोर्ट की मंजूरी से ही संभव होगा.

सैलरी कटने पर अब क्या कह रहे कर्मचारी?

कई कर्मचारियों पर अचानक से इस फैसले का असर पड़ा. जिन कर्मचारियों को अतिरिक्त इन्क्रीमेंट मिले थे, उनकी सैलरी में एक झटके में भारी कटौती हो गई. कई कर्मचारियों ने बताया कि उन्होंने बढ़ी हुई सैलरी को आधार बनाकर घर या कार लोन ले लिया था, ऐसे में अचानक वेतन घटने से उनका बजट बिगड़ गया. कुछ मामलों में कर्मचारियों की मासिक सैलरी 30 से 40 हजार रुपये तक कम हो गई।

कुछ कर्मचारियों ने नाराजगी जताते हुए आरोप लगाया कि एक-दो रजिस्ट्रारों ने तत्कालीन सीजेआई को गलत जानकारी दी, जिसके आधार पर इन्क्रीमेंट दिए गए. वहीं, कई कर्मचारियों का मानना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला लेना ही था, तो अतिरिक्त वेतनवृद्धि को भविष्य के सालाना इन्क्रीमेंट में समायोजित किया जा सकता था, ताकि अचानक वेतन कटौती का झटका न लगे।

फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को प्रशासनिक पारदर्शिता और समानता की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है, हालांकि इससे जुड़े मानवीय और आर्थिक पहलुओं पर कर्मचारियों के बीच असंतोष भी साफ नजर आ रहा है।

गुजरात के पत्रकार महेश लांगा को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम ज़मानत मिली

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (15 दिसंबर) को 'द हिंदू' के पत्रकार महेश लांगा को अंतरिम जमानत दी है. लांगा को पिछले साल अक्टूबर में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था।

लांगा 14 महीने से ज़्यादा समय से साबरमती जेल में बंद हैं.

जमानत की शर्त के तौर पर देश के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने लांगा को उनके खिलाफ लगे आरोपों से जुड़े कोई भी लेख लिखने से रोक लगाई है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल कोर्ट को बाकी नौ गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए रोज़ाना सुनवाई करने का भी निर्देश दिया है. लांगा को कार्यवाही में पूरा सहयोग करने और इस आधार पर कोई स्थगन न मांगने का आदेश दिया गया है कि मामले को रद्द करने की उनकी याचिका लंबित है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को इन निर्देशों के पालन पर एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है. मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी. ज्ञात हो कि लांगा को पिछले साल गुजरात पुलिस ने कथित जीएसटी धोखाधड़ी के आरोपों से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया था और बाद में उन पर कई मामले दर्ज किए गए. बाद में ईडी ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत केस दर्ज किया था.

लांगा की याचिका का विरोध करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आरोप लगाया कि लांगा ने, यह दावा करते हुए कि अगर भुगतान नहीं किया गया तो आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित की जाएगी धन उगाही की थी. मेहता ने कोर्ट से कहा, 'एक पत्रकार वसूली करते हुए पाया गया है... हम एक अतिरिक्त आरोप दाखिल करना चाहते हैं.' लांगा की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इस कदम पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ईडी अपना रुख बदलना चाह रही है. उन्होंने तर्क दिया कि '68 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी' के आरोप बढ़ा-चढ़ाकर बताए गए हैं. उन्होंने यह जोड़ा कि 'यह राशि 68 लाख रुपये भी नहीं है.' सिब्बल ने आगे कहा कि पीएमएलए केस का आधार बनने वाले मूल अपराध में कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है. उन्होंने गवाहों को प्रभावित करने के आरोपों को 'हैरान करने वाला' बताते हुए अपने मुवक्किल की तरफ से कहा, 'मैं अक्टूबर 2024 से हिरासत में हूं. किस अपराध के लिए? यह हत्या का मामला नहीं है.' सिब्बल ने यह भी आरोप लगाया कि बचाव पक्ष को महत्वपूर्ण दस्तावेज नहीं दिए गए हैं. उनका कहना था कि कोई सप्लीमेंट्री शिकायत नहीं थी और अभियोजन पक्ष 'अपनी मनमर्जी से नहीं चल सकता।'

इसके बाद अदालत ने इस पहलू को मद्देनजर रखते हुए कि सिर्फ़ नौ गवाहों से पूछताछ बाकी है, लांगा को अंतरिम ज़मानत दे दी. आदेश के बाद संक्षिप्त बातचीत के दौरान सॉलिसिटर मेहता ने जबरन वसूली के आरोप को दोहराया, जिस पर सिब्बल ने जवाब देते हुए कहा कि उद्योगपति पत्रकारों को निशाना बना रहे हैं. जिस पर मेहता ने किसी भी राजनीतिक मकसद से इनकार किया, और कहा कि अभियोजन पक्ष पूरी तरह पेशेवर तरीके से काम कर रहा है. जब यह बहस बढ़ी, तो सीजेआई ने दखल देते हुए इस बात पर ज़ोर दिया कि ट्रायल में देरी नहीं होनी चाहिए, साथ ही लांगा को पत्रकार के तौर पर अपने पद का गलत इस्तेमाल न करने की चेतावनी दी. सिब्बल ने जवाब दिया कि ऐसा कोई भी उल्लंघन ज़मानत रद्द करने का आधार होगा. इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने लांगा को ज़मानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।

संक्षिप्त ख़बरें

दर्दनाक सड़क हादसा: वाहन की टक्कर से मां-बेटे की मौत, एक महिला बुरी तरह घायल

बाराबंकी- यूपी के बाराबंकी में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां पर जिले में सोमवार सुबह लखनऊ-गोंडा राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने एक कार को टक्कर मार दी, जिससे कार में सवार मां-बेटे की मौत हो गई और एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई।

कैसे हुआ हादसा?

पुलिस के अनुसार, घटना थाना मसौली क्षेत्र के ग्राम बिरौली के पास उस वक्त की है जब संतोष कुमार मिश्रा (50) अपनी मां शांति देवी (75) और अन्य महिला संतोषी देवी के साथ कार से अपने घर श्रावस्ती जा रहे थे। थाना प्रभारी अमित प्रताप सिंह ने बताया कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और अनियंत्रित होकर सड़क किनारे जा गिरी। उन्होंने बताया कि मिश्रा और शांति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल संतोषी देवी का उपचार किया जा रहा है।

कार को गैस कटर से काटकर शव निकाले

पुलिस ने बताया कार को गैस कटर की मदद से काटकर फंसे शवों को बाहर निकाला गया और हादसे के बाद लखनऊ-गोंडा राष्ट्रीय राजमार्ग पर काफी देर तक जाम लग गया। उन्होंने बताया कि क्षतिग्रस्त वाहन को सड़क से हटाकर सामान्य यातायात बहाल कराया गया। सीसीटीवी फुटेज के जरिए अज्ञात वाहन की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

'वोट चोरी' के मुद्दे से उमर अब्दुल्ला का किनारा, बोले- इंडिया गठबंधन का इससे कोई लेना-देना नहीं

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

एक तरफ कांग्रेस वोट चोरी के मुद्दे पर मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है, तो वहीं इंडिया गठबंधन में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस मुद्दे से खुद को अलग कर लिया है. सोमवार को जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वोट चोरी' कांग्रेस का मुद्दा है और इंडिया गठबंधन में शामिल दलों का इससे कोई लेना-देना नहीं है. मुख्यमंत्री उमर का ये बयान ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक वोट चोरी के मुद्दे पर सत्ता को घेर रही है. उमर साफ कह दिया कि वोट चोरी का मुद्दा कांग्रेस का है और इंडिया गठबंधन का इससे कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने ये भी कहा कि हर राजनीतिक दल को अपना एजेंडा तय करने की आजादी है।

'वोट चोरी और SIR कांग्रेस का मुद्दा है'

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वोट चोरी और मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को अपना मुख्य मुद्दा बनाया है, ऐसे में हम उन्हें कुछ कहने वाले कौन होते हैं. उमर की नेशनल कॉन्फ्रेंस विपक्षी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस (इंडिया) गठबंधन में एक घटक है. लोकसभा में विपक्षी सांसदों की संख्या के हिसाब से कांग्रेस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है।

वोट चोरी पर दिल्ली में कांग्रेस की रैली

बीते रविवार को ही कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वोट चोरी' के मुद्दे को लेकर रैली की थी. इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी , प्रियंका गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए थे. रैली के दौरान कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा. नेताओं ने आरोप लगाया कि वोट चोरी सत्ताधारी पार्टी के डीएनए में है और उसके नेता गद्दार हैं जो लोगों के मतदान के अधिकार को छीनने की साजिश रच रहे हैं. कांग्रेस ने कहा कि ऐसे लोगों को सत्ता से हटाया जाना चाहिए. कांग्रेस ने दावा किया है कि पार्टी ने वोट चोरी के खिलाफ करीब छह करोड़ हस्ताक्षर एकत्र किए हैं और वह इन्हें भारत के राष्ट्रपति को सौंपेगी।

'वोट चोरी करने वाले गद्दार'

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने रामलीला मैदान में आयोजित रैली में कहा कि वोट चोरी करने वाले गद्दार हैं और इन्हें सत्ता से हटाना होगा ताकि वोट के अधिकार और संविधान को बचाया जा सके. उन्होंने ये दावा भी किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आरएसएस और मनुस्मृति की विचारधारा पर आगे बढ़ रहे हैं जिससे देश खत्म हो जाएगा. उन्होंने कहा कि देश को बचाना है, वोटों को सुरक्षित रखना है, संविधान को बचाना है तो लोगों को कांग्रेस एवं राहुल गांधी के साथ खड़ा होना होगा।

गुप्त वादे, खुली बेचैनी: कर्नाटक में कांग्रेस, आलाकमान के अनिर्णय का शिकार

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

राष्ट्रीय स्तर पर अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता को बरकरार रखने के लिए जद्दोजहद में लगी कांग्रेस के लिए कर्नाटक महज एक और राज्य भर नहीं है. यह सत्तारूढ़ कांग्रेस के लिए एक ऐसी एकमात्र मिसाल है, जहां न केवल उसकी पूर्णकालिक सरकार काम कर रही है, बल्कि उसके शासन के नतीजे भी जमीन पर दिखाई दे रहे हैं. ऐसे में तकाजा तो यही था कि पार्टी आलाकमान राज्य के सियासी मामलों को असाधारण दूरदर्शिता, समझबूझ और एहतियात के साथ संभालता. लेकिन हुआ इसका उलटा. पार्टी नेतृत्व एक बार फिर किंकर्तव्यविमूढ़ नजर आ रहा है. 2023 में राज्य में सियासी संतुलन बनाए रखने के लिए किए गए सत्ता-साझेदारी के उस कथित 'गुप्त' वादे को लेकर उसका इरादा क्या है, वह इसे साफ नहीं कर पा रहा है।

कर्नाटक में सियासी पारा इसलिए चढ़ा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस के अनेक कार्यकर्ता और कतिपय विधायक यह मानकर चल रहे हैं कि पार्टी ने डीके शिवकुमार को ढाई साल बाद मुख्यमंत्री बनाने का भरोसा दिया था. मगर जबकि आधा वक्त गुजर चुका है और 2026 नजदीक आते जा रहा है, वह कथित वादा अब भी अधर में लटका हुआ है. पार्टी आलाकमान न तो इसकी पुष्टि कर रहा है और न ही खंडन. इससे एक अजीब तरह की स्थिति पैदा हो गई हैं : सरकार ऊपर से तो कामकाज में लगी दिखती है, लेकिन भीतर ही भीतर उन सवालों के बोझ तले दबी भी है, जिनके जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं हैं।

कर्नाटक न पंजाब है, न मध्य प्रदेश और न राजस्थान - यहां दांव कहीं ऊंचे हैं

कर्नाटक को मध्य प्रदेश, राजस्थान या पंजाब की कतार में खड़ा नहीं किया जा सकता, जहां अंदरूनी गुटबाजी की वजह से कांग्रेस को अपनी सरकार से ही हाथ धोना पड़ा था. यहां दांव कहीं ऊंचे हैं. कर्नाटक देश की प्रौद्योगिकी राजधानी है. उत्तर भारत के बाहर सबसे बड़ा शहरी मध्यम वर्ग यहीं बसता है और यहां का राजनीतिक परिदृश्य दक्षिण भारत के गठबंधनों को सीधे तौर पर प्रभावित करता है. यहां पकड़ ढीली होने से केवल राज्य इकाई ही कमजोर नहीं होगी, बल्कि पार्टी

की साख को भी चोट पहुंचेगी और वह भी उस वक्त, जबकि उसे एक ठोस कामयाबी की सबसे ज्यादा दरकार है. इसमें कोई शक नहीं है कि सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली सरकार ने लोक कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर मजबूती से लागू किया है. लेकिन डीके शिवकुमार ने नगर नियोजन मंत्री के तौर पर, खासकर राजधानी बेंगलुरु में सरकार को जो गतिशीलता प्रदान की है, उसकी अहमियत भी कोई कम नहीं है. चाहें ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी का कायाकल्प करना हो, बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्यों के समन्वयन में सुधार करना हो या कभी सरकार के मुखर आलोचक रहे उद्योग जगत के लीडर्स के साथ संवाद स्थापित करना हो, ये कोई मामूली उपलब्धियां नहीं हैं. इससे उस सरकार के प्रति भरोसा दोबारा कायम करने में मदद मिली है, जिसे विरासत में एक अस्त-व्यस्त सिविक इकोसिस्टम मिला था।

सरकारी कामकाज में बाधा बन रही है अनिर्णय की स्थिति

कांग्रेस आलामान को मानना चाहिए कि इतने बड़े स्तर के सुधार एक स्पष्ट कमान-व्यवस्था के बिना संभव नहीं हैं. जब वरिष्ठ मंत्रियों और विभागों को नेतृत्व में बदलाव के संकेत मिलने लगते हैं तो शासन-व्यवस्था की रफ्तार अपने आप धीमी पड़ जाती है. इस अनिश्चितता का खामियाजा भी नजर आने लगा है. जिन फैसलों में हफ्तों का वक्त लगना चाहिए, उनमें महीनों लग रहे हैं और मंत्री भी नेतृत्व के इस मसले के निपटान तक साहसिक पहल उठाने से बच रहे हैं. इसका राष्ट्रीय आयाम भी उतना ही महत्वपूर्ण है. बिहार में मिली पराजय के बाद कांग्रेस के सामने यह साबित करने की चुनौती है कि वह आपसी खींचतान और गुटबाजी से ऊपर उठकर सरकार चला सकती है. कर्नाटक उसके लिए सबसे बड़ा अवसर है, जहां पार्टी यह दिखा सकती है कि वह कठिन फैसलों को अनिश्चितकाल तक टालने के बजाय उन्हें लेने का राजनीतिक साहस रखती है. मगर दिल्ली की चुप्पी का हर गुजरता दिन इस धारणा को और मजबूत कर रहा है कि पार्टी अब भी केंद्रीय नेतृत्व द्वारा फैसलों को टालने की पुरानी प्रवृत्ति से उबर नहीं पाई है।

कांग्रेस आलाकमान कर्नाटक में पनप रही इस बेचैनी को महज एक वहम मानकर नहीं चल सकता. यह हवाईअड्डों तथा जिला स्तरीय कार्यक्रमों में गूंजते नारों और पार्टी से निरंतरता व दृढ़ता दिखाने की उम्मीद रखने वाले विधायकों की दबी-जुबान की गई टिप्पणियों में साफ झलकती है. अब और देरी से इस बेचैनी के नाराजगी में बदलने का खतरा पैदा हो सकता है।

अब दो ही विकल्प : स्पष्ट फैसला या दुर्दशा का इंतजार

कर्नाटक में कांग्रेस के पास यह दिखाने का मौका है कि वह पूरे अनुशासन के साथ बेखटके सरकार चला सकती है. इस समय पार्टी के पास दो ही रास्ते हैं. पहला, पार्टी हाईकमान आगे बढ़कर राज्य में नेतृत्व के मसले को सुलझाए और असमंजस की स्थिति को स्थिरता में बदल दें. या फिर, जो जैसा है, वैसा ही चलने दे और अपने सबसे मजबूत गढ़ में दुर्दशा की कहानी को दोहराने के लिए तैयार रहे।

राजस्थान के ष्टरूभजन लाल शर्मा का हेलीकॉप्टर आपात स्थिति में कराई गई लैंडिंग

आगरा- राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का हेलीकॉप्टर सोमवार को मौसम खराब होने के कारण आगरा के खेरिया हवाई अड्डे पर आपात स्थिति में उतारा गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अपर जिलाधिकारी (प्रोटोकॉल) प्रशांत तिवारी ने बताया कि मुख्यमंत्री शर्मा हेलीकॉप्टर से राजस्थान के भरतपुर जा रहे थे, लेकिन खराब मौसम के कारण पायलट को हेलीकॉप्टर को आगरा की ओर मोड़ना पड़ा। हेलीकॉप्टर ने जयपुर से उड़ान भरी थी। अधिकारियों के अनुसार, हेलीकॉप्टर दोपहर करीब साढ़े 12 बजे खेरिया हवाई अड्डे पर उतरा, जहां मुख्यमंत्री को लगभग एक घंटे तक इंतजार करना पड़ा। तिवारी ने बताया कि मौसम में सुधार होने के बाद हेलीकॉप्टर ने भरतपुर के लिए यात्रा फिर से शुरू की। राजस्थान के भरतपुर और उत्तर प्रदेश के आगरा के बीच करीब 60 किलोमीटर की दूरी है और दोनों की सीमाएं आपस में सटी हुई हैं।

न्यायपालिका पर नकेल डालने का सियासी प्रयोग है महाभियोग

मद्रास हाइकोर्ट के न्यायाधीश के एक फैसले को लेकर देश की राजनीति में हलचल मची हुई है। अब विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के 107 सांसदों ने मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन को पद से हटाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक महाभियोग प्रस्ताव सौंपा है । इस प्रस्ताव में कांग्रेस, डीएमके आप , सपा, सीपीआई, सीपीएम, और शिवसेना (उद्धव ठाकरे) सहित कई प्रमुख दलों के सांसदों के हस्ताक्षर हैं। नियम के अनुसार, किसी जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश करने के लिए लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है,इंडिया ब्लॉक के 107 सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव पर दस्तखत किए हैं।

आपको बता दें कि इस पूरे राजनीतिक विवाद की पृष्ठभूमि में न्यायमूर्ति स्वामीनाथन का एक फैसला है। पिछले हफ्ते, उन्होंने तमिलनाडु के तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित 6वीं शताब्दी के सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के प्रशासन को एक निर्देश दिया। यह निर्देश था कि 13वीं शताब्दी की सिकंदर बादुशाह दरगाह के पास एक स्तंभ पर 'दीपक जलाने की परंपरा' को फिर से शुरू किया जाए। जब राज्य सरकार ने विरोध किया और मंदिर प्रबंधन ने पालन नहीं किया, तो जज ने अवमानना का आदेश भी जारी किया।न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने अपने आदेशों का पालन न करने पर तमिलनाडु के मुख्य सचिव और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) को 17 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होने के लिए भी तलब किया है। उन्होंने राज्य सरकार के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा, 'मैं यहां हाथ उठाकर असहाय होकर यह कहने के लिए नहीं हूं कि, 'हे पिता, उन्हें माफ कर दो, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं।' यह जानबूझकर उल्लंघन है।' उन्होंने केओसुबल की रिपोर्ट का संज्ञान लिया, जिसमें बताया गया था कि मदुरै पुलिस आयुक्त ने 200 से अधिक पुलिसकर्मियों के साथ अदालत के आदेश का पालन करने से केओसुबल टुकड़ी को रोका था।

दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्टों के 56 पूर्व न्यायाधीशों ने विपक्षी सांसदों द्वारा मद्रास हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग की पहल को लेकर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पूर्व न्यायाधीशों ने कहा कि यह कदम उन न्यायाधीशों को दबाव में लाने का प्रयास है जो राजनीतिक या वैचारिक उम्मीदों के अनुरूप फैसले नहीं देते। 12 दिसंबर को जारी संयुक्त बयान में उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास लोकतंत्र और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बुनियाद को कमजोर करते हैं। उन्होंने कहा कि महाभियोग का इस्तेमाल न्यायिक आचरण की रक्षा के लिए होता है, न कि राजनीतिक हथियार की तरह।

मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन को हटाने की मांग करते हुए 100 से अधिक सांसदों की ओर से लाए गए महाभियोग प्रस्ताव के खिलाफ बड़ा विरोध सामने आया. 50 से अधिक पूर्व न्यायाधीशों, जिनमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और कई हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश शामिल हैं, ने एक कड़े शब्दों वाला पत्र जारी कर इस कदम की कड़ी निंदा की. उन्होंने इस कदम को जजों को डराने-धमकाने की खुली कोशिश बताया.पूर्व जजों ने कहा कि कार्तिगई दीपम दीप-प्रज्वलन मामले में दिए गए निर्णय के आधार पर जस्टिस स्वामीनाथन को हटाने की कोशिश लोकतंत्र और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की जड़ें हिला देने वाली है. उन्होंने लिखा कि सांसदों द्वारा बताए गए कारण सतही और इतने गंभीर संवैधानिक कदम के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं हैं.

पत्र में पूर्व जजों ने इस कोशिश को न्यायपालिका को कमजोर करने वाली लंबी और चिंताजनक राजनीतिक परंपरा का हिस्सा बताया. उन्होंने आपातकाल के बाद तीन वरिष्ठ जजों की सुपरसिडिंग, जस्टिस एचआर खन्ना की उपेक्षा और पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, एसए बोबडे, डीवाई चंद्रचूड़ और अब सीजेआई सूर्याकांत के खिलाफ चलाए गए राजनीतिक अभियान का उल्लेख किया.

पूर्व न्यायाधीशों ने चेतावनी दी कि महाभियोग जैसे संवैधानिक प्रावधान का इस्तेमाल आर्म-ट्विस्टिंग और बदले की राजनीति के हथियार के रूप में नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा, 'आज निशाना एक जज है, कल पूरा संस्थान निशाने पर होगा. '

पूर्व जजों ने सांसदों, बार कार्उसिल, सिविल सोसाइटी और नागरिकों से अपील की कि इस कदम को शुरुआत में ही रोक दिया जाए, क्योंकि जज संविधान के प्रति जवाबदेह होते हैं, न कि राजनीतिक समूहों की पसंद-नापसंद के प्रति कोई जवाबदेही

बता दें कि यह पूरा विवाद तमिलनाडू में तब उठा, जब जस्टिस स्वामीनाथन ने तिरुप्परंकुंद्रम हिल पर दीपथून स्तंभ पर कार्तिगई दीपम का दीप जलाने का आदेश दिया. यह स्थान सिकंदर बादूशा दरगाह के पास है और लंबे समय से संवेदनशील माना जाता रहा है. याचिकाकर्ताओं की मांग पर जज ने 4 दिसंबर शाम 6 बजे तक दीप जलाने का निर्देश दिया. उन्होंने दलील दी कि यह कदम मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता, लेकिन दीप न जलाने से पहाड़ी पर मंदिर के अधिकार कमजोर हो सकते हैं, क्योंकि वहां कथित अतिक्रमण की शिकायतें उठती रही हैं.

हालांकि तमिलनाडू सरकार ने यह कहते हुए कि इससे कानून-व्यवस्था बिगड़ सकती है, आदेश लागू करने से इनकार कर दिया. इसके बाद पुलिस और हिंदू संगठनों के बीच झड़पें भी हुई. डीएमके ने आरोप लगाया कि जज ने 2017 की डिवीजन बेंच के आदेश को उलट दिया है और उनका निर्देश चुनाव से ठीक पहले सांप्रदायिक तनाव भड़का सकता है. पार्टी नेता टीआर बालू ने लोकसभा में यह मुद्दा उठाते हुए दावा किया कि बीजेपी राज्य में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है.

वहीं तमिलनाडू बीजेपी अध्यक्ष नैनार नागेन्द्रन ने महाभियोग प्रस्ताव को लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया. उन्होंने कहा कि डीएमके न्यायिक फैसले तभी स्वीकार करती है जब वे उसके हित में हों. भाजपा नेता ने कहा कि जस्टिस स्वामीनाथन ने कोई अपराध नहीं किया और मंदिर व पुलिस प्रशासन की विफलता के कारण ही उन्हें आदेश देना पड़ा. उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह के महाभियोग प्रयास गलत परंपरा कायम करेंगे और संस्थानों के बीच टकराव को जन्म दे सकते हैं.

आपको पता रहे यह मुद्दा सिर्फ अदालत तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पिछले हफ्ते लोकसभा में भी बवाल मच गया था। डीएमके सदस्यों ने सदन में विरोध प्रदर्शन करते हुए बीजेपी पर 'सांप्रदायिक तनाव' भड़काने का आरोप लगाया। वहीं, केंद्रीय उपमंत्री एल. मुरुगन ने डीएमके पर 'एक विशेष समुदाय को निशाना बनाने' का पलटवार किया। डीएमके सांसद टीआर बालू ने सदन में न्यायमूर्ति स्वामीनाथन के 'एक विशेष विचारधारा' के प्रति निष्ठा रखने की आलोचना की, जिस पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने न्यायपालिका पर आक्षेप न लगाने की चेतावनी दी थी। अब स्पीकर ओम बिरला के सामने इन आरोपों की जांच और प्रस्ताव पर निर्णय लेने की बड़ी जिम्मेदारी है।देखना है कि इस मामले का पटाक्षेप किस तरह होता है।

मनोज कुमार अग्रवाल

पंजाब भूजल में यूरेनियम संदूषण संकट: 62.5% नमूने सुरक्षित सीमा से अधिक हैं

पंजाब को एक चिंताजनक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) के हालिया आंकड़ों से इसके भूजल में यूरेनियम संदूषण के अभूतपूर्व स्तर का पता चलता है। नवीनतम वार्षिक भूजल रिपोर्ट 2025 के अनुसार, राज्य ने पूरे देश में यूरेनियम संदूषण की सबसे अधिक तीव्रता दर्ज की है। सीजीडब्ल्यूबी रिपोर्ट (2025) से प्रमुख निष्कर्ष संदूषण दरः मानसून के मौसम के बाद पंजाब में एकत्रित भूजल नमूनों का 62.5% यूरेनियम की स्वीकार्य सुरक्षित सीमा से अधिक था। यह मानसून से पहले 53.04% नमूनों की तुलना में तेज वृद्धि है। पिछले वर्ष की तुलनाः स्थिति नाटकीय रूप से बिगड़ गई है, सुरक्षित सीमा का उल्लंघन करने वाले नमूनों का अनुपात 2024 में 32.6% से बढ़कर 91.7% से अधिक हो गया है। सुरक्षित सीमा का उल्लंघनः विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) दोनों द्वारा निर्धारित पेयजल में यूरेनियम के लिए अनुमेय सीमा, 30 पार्ट्स प्रति बिलियन (पीपीबी) या 0.03झटेक्स्ट6एमजी/एल8 है। दूषित क्षेत्रः पंजाब के 23 जिलों में से 16 को दूषित क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। संगरूर और बठिंडा जैसे सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में यूरेनियम की सांद्रता 200 पीपीबी से अधिक दर्ज की गई है, जो सुरक्षित सीमा से लगभग सात गुना है। प्रभावित जिलेः दूषित क्षेत्रों में तरन तारण, पटियाला, संगरूर, मोगा, मानसा, बरनाला, लुधियाना, जालंधर, कपूरथला, फिरोज़ेपुर, फजिल्का, फ़तेहगढ़ साहिब, फरीदकोट, अमृतसर, मुख्तार, और बठिंडा शामिल हैं। स्वास्थ्य और पर्यावरणीय प्रभाव यूरेनियम की उच्च सांद्रता सार्वजनिक स्वास्थ्य और राज्य के कृषि के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालः उच्च यूरेनियम स्तर वाले पानी का दीर्घकालिक सेवन मुख्य रूप से इसकी रासायनिक विषाक्तता से जुड़ा हुआ है, जो गुर्दे की बीमारियों, कैंसर और अन्य पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। मालवा क्षेत्र में पिछले अध्ययनों ने भी प्रदूषण को ऑटिज्म और सेरेब्रल पाल्सी जैसे न्यूरोलॉजिकल विकारों से जोड़ा है। पर्यावरणीय कारणः यूरेनियम की उपस्थिति को कई कारकों के संयोजन से जोड़ा जाता है, जिनमें शामिल हैं जियोजेनिक कारकः क्षेत्र में प्राकृतिक भूवैज्ञानिक स्थितियाँ। भूजल क्षयः भूजल का अत्यधिक निष्कर्षण जलभृत रसायन विज्ञान को बदल देता है, जिससे प्राकृतिक रूप से होने वाले यूरेनियम की लामबंदी और रिलीज हो सकती है। मानवजनित गतिविधियाँः कृषि में फॉस्फेट उर्वरकों का बड़े पैमाने पर उपयोग एक प्रमुख योगदान कारक है, क्योंकि इन उर्वरकों में यूरेनियम की ट्रेस सांद्रता पाई जाती है। कृषि खतराः रिपोर्ट में अन्य प्रदूषकों पर भी ध्यान दिया गया है, जैसे अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट और 25% नमूनों में लवणता बढ़ना, जो भूमि के क्षरण और मिट्टी की उर्वरता में कमी का कारण बन रहे हैं। तत्काल कार्रवाई के लिए आह्वान केंद्रीय सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग के साथ संसद में संकट उठाया गया है। प्रमुख प्रस्तावित कार्यों में शामिल हैंः 'विशेष भूजल शमन मिशन' का शुभारंभः जल संदूषण आपदा से निपटने के लिए एक समर्पित मिशन।

आरओ-आधारित सामुदायिक प्रणालियों की युद्ध-पैर स्थापनाः सभी प्रभावित गांवों में जल शोधन प्रणाली तैनात करना। स्क्रीनिंग कैंपः रोग प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य जांच और परीक्षण शिविर स्थापित करना। औपचारिक मान्यताः समर्पित वित्तपोषण और राहत प्रयासों को सुव्यवस्थित करने के लिए यूरेनियम को एक प्रमुख भूजल दूषित पदार्थ के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देना। यह बढ़ता हुआ संदूषण न केवल पंजाब में लाखों लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डालता है, बल्कि राज्य की मुख्य रूप से कृषि अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक खतरा भी पैदा करता है।

डॉ विजय गर्ग

भारत के बढ़ते कदमां के पीछे वैचारिक प्रबुद्धता, योजना और समेकित दृढ़ संकल्प

यह भारत के बढ़ते कद के नेपथ्य में कुशल नेतृत्व, सामूहिक चेतना और प्रगतिशील विचारों की उस दीर्घ साधना का फल है, जिसकी जड़ें इतिहास में हैं और शाखाएँ भविष्य तक फैली हुई हैं, भारत आज विश्व-पटल पर केवल एक उभरती शक्ति नहीं बल्कि एक ऐसी निर्णायक उपस्थिति बन चुका है। जिसे अनदेखा करना किसी भी राष्ट्र के लिए संभव नहीं रहा, यह काल किसी एक सरकार, एक व्यक्ति या एक विचारधारा का नहीं बल्कि उस राष्ट्रीय चेतना का है जो सदियों के आत्मसंघर्ष, आत्मचिंतन और आत्मबल से परिपक्व हुई है, मैं स्वयं को किसी राजनीतिक दल का समर्थक नहीं मानता, किंतु यह तथ्य निर्विवाद है कि आज भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा, कूटनीतिक प्रभाव और आत्मविश्वास ऐतिहासिक ऊँचाइयों को छू रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षणों में भारतीय प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का आँकड़ा किसी व्यक्ति की प्रशंसा भर नहीं बल्कि उस विश्वास का प्रमाण है जो विश्व समुदाय भारत की स्थिरता, लोकतांत्रिक परिपक्वता और विकास-दृष्टि पर कर रहा है, महात्मा गांधी ने कहा था कि 'राष्ट्र की वास्तविक पहचान उसकी आत्मा से होती है,' और आज भारत की आत्मा विज्ञान, तकनीक, करुणा, सहअस्तित्व और नवाचार के संतुलन से आलोकित दिखाई देती है, डिजिटल इंडिया के माध्यम से जिस प्रकार भारत ने तकनीक को अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुँचाया है वह केवल प्रशासनिक सफलता नहीं बल्कि लोकतंत्र के विस्तार की ऐतिहासिक घटना है, विश्व बैंक, आईएमएफ और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टों में भारत को विकासशील देशों के लिए प्रेरणा बताया जाना इस बात का संकेत है कि भारत अब सीखने वाला नहीं बल्कि मार्ग दिखाने वाला राष्ट्र बन चुका है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता के समय कहा था कि 'हम नियति से साक्षात्कार कर रहे हैं,' और आज वह साक्षात्कार एक नए रूप में हमारे सामने खड़ा है, 1951 से आरंभ पंचवर्षीय योजनाओं ने जिस नियोजनशील दृष्टि को जन्म दिया, 1991 के आर्थिक सुधारों ने उसे वैश्विक पंख दिए और नीति आयोग ने उसे नवाचार व प्रतिस्पर्धा की नई दिशा प्रदान की, अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का यह कथन कि 'विकास का अंतिम उद्देश्य मानव स्वतंत्रता का विस्तार है,' भारत की विकास यात्रा में सजीव होता दिखाई देता है, विशाल जनसंख्या जिसे कभी बोझ कहा जाता था आज वही भारत की सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरी है, स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को राष्ट्र की रीढ़ बताते हुए कहा था कि 'उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत,' और भारत की युवा शक्ति आज इसी मंत्र को वैश्विक मंच पर चरितार्थ कर रही है, आईटी, सॉफ्टवेयर, अंतरिक्ष, जैव-प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप संस्कृति में भारत की छलांग यह प्रमाणित करती है कि यह देश केवल संसाधनों का उपभोक्ता नहीं बल्कि विचारों का उत्पादक बन चुका है, सुंदर पिचाई, सत्य नडेला, इंदिरा नूई, अरविंद कृष्णा जैसे वैश्विक नेतृत्वकर्ता भारतीय मस्तिष्क की उसी परंपरा के वाहक हैं जिसे आचार्य चाणक्य ने नीति और विवेक का आधार बताया था, उद्योग जगत में टाटा, अंबानी और मित्तल जैसे नाम यह सिद्ध करते हैं कि भारतीय उद्यमिता अब आत्मविश्वास के साथ विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा कर रही है, रतन टाटा के शब्दों में 'जोखिम उठाए बिना प्रगति असंभव है,' और भारत ने अब जोखिम से भय नहीं बल्कि अवसर का निर्माण करना सीख लिया है, रक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में पोखरण से लेकर अंतरिक्ष अभियानों तक भारत की उपलब्धियाँ उस वैज्ञानिक चेतना का प्रमाण हैं जिसे डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने 'विकसित भारत का सपना' कहा था, असैन्य परमाणु समझौते और रणनीतिक साझेदारियों ने यह स्थापित किया कि भारत विश्व शांति और संतुलन का उत्तरदायी भागीदार है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भारत की बहुस्तरीय कूटनीति–चाहे वह अमेरिका हो, रूस, जापान, फ्रांस, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया–वसुधैव कुटुम्बकम् की उस भावना को साकार करती है जिसे भारतीय दर्शन ने सहस्राब्दियों पहले उद्घोषित किया था, दावोस में विश्व आर्थिक मंच से लेकर जी-20 जैसे वैश्विक मंचों पर भारत की भूमिका यह संकेत देती है कि यह देश अब केवल प्रतिक्रियाशील नहीं बल्कि दिशा-निर्देशक बन चुका है, सैमुअल हंटिंगटन का यह कथन कि इक्कीसवीं सदी का संतुलन एशिया में तय होगा, आज भारत-केंद्रित होता प्रतीत हो रहा है, जनसांख्यिकीय लाभ, तीव्र जीडीपी वृद्धि और नवाचार की गति भारत को दीर्घकालीन स्थिरता प्रदान कर रही है, लोकतंत्र जिसकी जड़ें ग्रामसभा से लेकर संसद तक फैली हैं आज विश्व के लिए एक जीवंत उदाहरण है कि विविधता कैसे शक्ति बनती है, डॉ. भीमराव आंबेडकर ने संविधान को सामाजिक न्याय का औजार बताया था और आज वही संविधान भारत की प्रगति का नैतिक आधार बना हुआ है, साहित्य, संस्कृति और विचार के क्षेत्र में भी भारत की उपस्थिति सशक्त है,

नोबेल विजेता रामकृष्णन से लेकर अमर्त्य सेन तक और वैश्विक साहित्य में भारतीय मूल के लेखकों की स्वीकार्यता यह दर्शाती है कि भारत की आवाज केवल आर्थिक नहीं बल्कि वैचारिक भी है, रवींद्रनाथ ठाकुर ने जिस विश्वमानव की कल्पना की थी आज भारत उसी विचार का वाहक बनता दिखाई दे रहा है, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं कि भारत अब केवल भविष्य का स्वप्न नहीं बल्कि वर्तमान की सशक्त वास्तविकता है, यह स्वर्णिम काल तभी सार्थक रहेगा जब यह विकास करुणा, समावेशिता और नैतिकता से जुड़ा रहेगा, क्योंकि जैसा कि महात्मा गांधी ने चेताया था, 'नैतिकता के बिना प्रगति विनाश का कारण बन जाती है,' आज भारत के उत्थान की यह गाथा विश्व को यह संदेश दे रही है कि शक्ति का अर्थ प्रभुत्व नहीं बल्कि उत्तरदायित्व है, और इसी उत्तरदायित्व के साथ भारत वैश्विक मंच पर विचार, तकनीक और कूटनीति का सूत्रधार बनकर उभरा है, जहाँ से यह उद्घोष सुनाई देता है कि भारत अब भविष्य नहीं, बल्कि वर्तमान का नेतृत्व कर रहा है।

संजीव ठाकुर

संपादकीय

सावरकर की चेतना और भागवत का समकालीन राष्ट्रबोध

[राष्ट्र के लिए मरने से आगे: जीने की वैचारिक क्रांति]

[नए युग की राष्ट्रभक्तिः न मरने का आग्रह, न जीने का भय]

अंडमान की वह ऐतिहासिक भूमि, जहाँ स्वतंत्रता संग्राम की वेदना आज भी समुद्री हवाओं में मौन होकर गूंजती है, एक बार फिर राष्ट्रचिंतन की साक्षी बनी। काला पानी की सेलुलर जेल केवल ईट-पत्थरों की संरचना नहीं, बल्कि उन असंख्य तपस्वी आत्माओं का अमिट स्मारक है, जिन्होंने भारतमाता की स्वतंत्रता के लिए अमानवीय यातनाओं को भी व्रत की भाँति स्वीकार किया। इसी पावन पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत का उद्घोष गूंजा– 'यह भारत के लिए जीने का समय है, मरने का नहीं।' यह कथन बलिदान की गौरवशाली परंपरा को नकारे बिना, राष्ट्रभावना को आत्मविनाश से निकालकर जीवन, निर्माण और पुनर्जागरण की दिशा में मोड़ने वाला स्पष्ट एवं सशक्त संदेश है।

दक्षिण अंडमान के बेओदनाबाद स्थित वीर सावरकर प्रेरणा पार्क में, वीर सावरकर की प्रतिमा के अनावरण अवसर पर दिया गया यह वक्तव्य इतिहास की पीड़ा को भविष्य की प्रेरणा में रूपांतरित करता प्रतीत हुआ। सावरकर का स्वप्न केवल विदेशी शासन से मुक्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि एक संगठित, आत्मविश्वासी और जाग्रत राष्ट्र के निर्माण का था। उसी तपोभूमि से भागवत जी ने यह स्पष्ट किया कि सच्चा राष्ट्रप्रेम आत्मोत्सर्ग की एकांगी व्याख्या नहीं, बल्कि सृजनशील, सकारात्मक और दीर्घकालीन जीवन-दृष्टि में निहित है–ऐसा जीवन, जो आने वाली पीढ़ियों को एक सशक्त, समर्थ और आत्मनिर्भर भारत का उत्तराधिकार सौंप सके।

आज का भारत एक अलग मोड़ पर खड़ा है। स्वतंत्रता के लिए प्राण देने का युग इतिहास बन चुका है, परंतु राष्ट्र के लिए जीने की चुनौती अब और अधिक व्यापक हो गई है। भागवत जी का संदेश इसी संदर्भ में सामयिक और प्रासंगिक बन जाता है। उन्होंने यह रेखांकित किया कि सावरकर ने कभी जाति, प्रांत या भाषा की सीमाओं में राष्ट्र को नहीं बांधा। अखंड भारत की उनकी परिकल्पना सांस्कृतिक एकता पर आधारित थी। आज जब छोटे-छोटे मुद्दों पर समाज को बांटने की कोशिशें होती हैं, तब यह स्मरण आवश्यक है कि हमारी पहली पहचान भारतीय होना है।

'टुकड़े-टुकड़े' की मानसिकता और विभाजनकारी शब्दावली पर करारा प्रहार करते हुए भागवत जी ने राष्ट्र को सर्वोपरि रखने का आह्वान किया। राष्ट्रभक्ति नारों या आक्रोश तक सीमित नहीं, बल्कि दैनिक आचरण, सहिष्णुता और सहयोग में प्रकट होती है। विविध मतों और परंपराओं के बावजूद एक साझा लक्ष्य की ओर बढ़ना ही भारत की असली शक्ति है। उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया कि आंतरिक एकता के बिना बाहरी चुनौतियों का सामना करना असंभव है। इसलिए राष्ट्र को हर प्रकार के संकीर्ण स्वार्थ से ऊपर उठाकर देखना समय की आवश्यकता है।

इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति ने संदेश को और व्यापक संदर्भ दिया। मंच से युवाओं को संबोधित करते हुए भागवत जी ने सफलता की नई परिभाषा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि आज का युवा विश्व की सबसे तेज़ी से उभरती अर्थव्यवस्था का भाग है। आगे बढ़ो, धन अर्जित करो, नवाचार करो, करियर में शिखर तक पहुंचो–लेकिन यह सब राष्ट्र के प्रति दायित्व को भूले बिना हो। साधुता या त्याग का अर्थ समाज से कटना नहीं, बल्कि अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ बनकर समाज को सशक्त करना है।

भागवत जी का यह दृष्टिकोण निराशा और हिंसा की प्रवृत्तियों से अलग राह दिखाता है। उन्होंने युवाओं को यह समझाया कि क्रांति केवल सड़कों पर नहीं होती, बल्कि प्रयोगशालाओं, कक्षाओं, खेतों, कारखानों और कार्यालयों में भी जन्म लेती है। सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक गौरव और पर्यावरण संरक्षण को राष्ट्रसेवा का अभिन्न अंग बताते हुए उन्होंने एक संतुलित विकास मॉडल की ओर संकेत किया। यह ऐसा विकास है, जिसमें प्रगति मानवता से कटकर नहीं, बल्कि उसके साथ कदम मिलाकर चलती है।

भारत की विविधता को अक्सर चुनौती के रूप में देखा जाता है, परंतु भागवत जी ने इसे शक्ति का स्रोत बताया। अनेक भाषाएं, असंख्य परंपराएं और विविध संस्कृतियां मिलकर एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करती हैं, जो विश्व को दिशा दे सकता है। जब दुनिया आर्थिक अनिश्चितताओं और संघर्षों से गुजर रही है, तब भारत के पास आशा का केंद्र बनने का अवसर है। इसके लिए आवश्यक है कि हम सावरकर के दर्द को केवल स्मृति न बनाएं, बल्कि उससे प्रेरणा लेकर स्वार्थ त्यागकर कार्य करें।

यह संदेश केवल विचारधारा का उद्घोष नहीं, बल्कि हर नागरिक के लिए आह्वान है। यदि शिक्षक शिक्षा से समाज को आलोकित करे, उद्यमी ईमानदारी से रोजगार सृजित करे, किसान प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर अन्न उपजाए और युवा तकनीक से देश को आगे बढ़ाए, तो भारत को रोक पाना किसी के लिए संभव नहीं होगा। भावनात्मक भाषण क्षणिक उत्साह देते हैं, किंतु स्थायी परिवर्तन अनुशासित और निरंतर प्रयास से ही आता है–यह बात भागवत जी ने स्पष्ट रूप से रेखांकित की। अंडमान से उठा यह स्वर आज पूरे देश में प्रतिध्वनित हो रहा है। यह हमें बताता है कि हमारा समय आ चुका है–निर्माण का, सृजन का और विजय का। मोहन भागवत का यह उद्बोधन नई राष्ट्रभक्ति की नींव रखता है, जहां अतीत के बलिदान सम्मानित हैं, पर भविष्य का मार्ग जीवन, एकता और प्रगति से प्रशस्त होता है। भारत आज तैयार है एक सशक्त, समृद्ध और संगठित राष्ट्र बनने के लिए। भारत के लिए जियो, ताकि विश्व हमारे अनुभव से सीख सके–यही इस जीवन-क्रांति का सार है।

प्रो. आरके जैन

भारत पर अब मेक्सिको का पचास फीसद टैरिफ हमला

मेक्सिको द्वारा भारत, चीन सहित अनेक एशियाई देशों से आने वाले उत्पादों पर पाँच से पचास प्रतिशत तक नए शुल्क लगाने का निर्णय केवल एक व्यापारिक नीति नहीं है, बल्कि बदलते वैश्विक शक्ति-संतुलन और बढ़ते संरक्षणवाद का स्पष्ट संकेत है। यह कदम उस दौर में उठाया गया है जब मुक्त व्यापार की अवधारणा धीरे-धीरे संदेह के घेरे में आ रही है और राष्ट्र अपने घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए सख्त नीतियाँ अपनाने लगे हैं। मेक्सिको की संसद से पारित यह निर्णय आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय व्यापार, विशेषकर विकासशील देशों की निर्यात संभावनाओं पर दूरगामी प्रभाव डाल सकता है।

मेक्सिको सरकार का तर्क है कि एशियाई देशों से सस्ते उत्पादों की बाढ़ ने उसके स्थानीय उद्योगों को गंभीर क्षति पहुँचाई है। वस्त्र, जूते, इस्पात, धातु, वाहन कलपुर्जे और उपभोक्ता वस्तुओं जैसे क्षेत्रों में स्थानीय उत्पादक प्रतिस्पर्धा में पिछड़ते चले गए। सरकार का मानना है कि ऊँचे शुल्क लगाकर घरेलू विनिर्माण को संजीवनी दी जा सकती है और रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। यह तर्क पहली नज़र में आकर्षक लगता है, परंतु इसका दूसरा पक्ष भी उतना ही गंभीर है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता।

भारत के लिए यह निर्णय विशेष चिंता का विषय है। बीते कुछ वर्षों में मेक्सिको भारत के लिए एक उभरता हुआ निर्यात बाजार बनकर सामने आया था। वाहन कलपुर्जे, दवाइयाँ, वस्त्र और कुछ औद्योगिक उत्पादों के निर्यात में लगातार वृद्धि हो रही थी। अब ऊँचे शुल्क लगने से भारतीय उत्पाद महंगे हो जाएंगे और उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर पड़ जाएगी। इसका सीधा असर निर्यातकों की आय, उत्पादन और रोजगार पर पड़ेगा। विशेष रूप से वाहन उद्योग, जो पहले ही वैश्विक मंदी और तकनीकी परिवर्तन के दबाव में है, इस झटके को झेलने में कठिनाई महसूस करेगा।

यह निर्णय केवल भारत तक सीमित नहीं है। चीन, जो मेक्सिको का एक बड़ा आपूर्तिकर्ता रहा है, इस नीति से सबसे अधिक प्रभावित होगा। दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और अन्य एशियाई देशों के लिए भी यह चेतावनी है कि वैश्विक व्यापार का वातावरण अब पहले जैसा उदार नहीं रहा। दरअसल, यह पूरा घटनाक्रम उस व्यापक प्रवृत्ति का हिस्सा है, जिसमें अमेरिका की नीतियों का प्रभाव उसके व्यापारिक साझेदारों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उत्तरी अमेरिका के क्षेत्रीय व्यापार समझौते के अंतर्गत मेक्सिको अमेरिकी बाजार पर अत्यधिक निर्भर है, और ऐसे में वह अमेरिकी दबावों की अनदेखी नहीं कर सकता। चीन विरोधी रुख और घरेलू उद्योगों को प्राथमिकता देने की सोच ने मेक्सिको को भी इसी दिशा में धकेल दिया है।

हालाँकि, संरक्षणवाद के ये उपाय अल्पकाल में कुछ स्थानीय उद्योगों को राहत दे सकते हैं, परंतु दीर्घकाल में इसके नकारात्मक परिणाम सामने आने की आशंका अधिक है। ऊँचे शुल्क उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं को महंगा बना देंगे, जिससे महंगाई बढ़ सकती है। आपूर्ति श्रृंखला में बाधाएँ उत्पन्न होंगी और उद्योगों की लागत बढ़ेगी। अंततः इसका बोझ आम नागरिक पर ही पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, व्यापारिक साझेदार देशों की ओर से प्रतिशोधात्मक कदम उठाए जाने की संभावना भी बनी रहती है, जिससे वैश्विक व्यापार युद्ध और गहराता चला जाएगा।

भारत के सामने इस स्थिति से निपटने के लिए कई स्तरों पर सोचने की आवश्यकता है। एक ओर सरकार को कूटनीतिक स्तर पर मेक्सिको से संवाद बढ़ाना होगा और द्विपक्षीय व्यापार समझौते की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार करना होगा। दूसरी ओर, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंचों पर अपने हितों की रक्षा के लिए कानूनी विकल्पों का भी आकलन करना पड़ेगा। साथ ही, भारतीय उद्योगों को केवल एक या दो बाजारों पर निर्भर रहने के बजाय अपने निर्यात का विविधीकरण करना होगा। लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और अन्य उभरते क्षेत्रों में नए अवसर तलाशना अब अनिवार्य हो गया है।

यह भी स्पष्ट है कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में केवल मुक्त व्यापार के भरोसे बैठना पर्याप्त नहीं होगा। घरेलू विनिर्माण को मजबूत करना, गुणवत्ता और नवाचार पर ध्यान देना तथा लागत प्रतिस्पर्धा बढ़ाना समय की माँग है। यदि भारतीय उत्पाद गुणवत्ता और मूल्य दोनों में मजबूत होंगे, तो ऊँचे शुल्कों के बावजूद वे अपना स्थान बना सकते हैं। इसके साथ ही, विदेशों में उत्पादन इकाइयाँ स्थापित करने जैसी रणनीतियों पर भी विचार किया जा सकता है, जिससे शुल्क बाधाओं को आंशिक रूप से पार किया जा सके।

मेक्सिको का यह कदम इस बात की भी याद दिलाता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था अब सहयोग से अधिक प्रतिस्पर्धा की ओर बढ़ रही है। राष्ट्र अपने-अपने हितों को सर्वोपरि मानकर नीतियाँ बना रहे हैं। ऐसे में विकासशील देशों के लिए चुनौतियाँ बढ़ना स्वाभाविक है। यदि यह प्रवृत्ति जारी रही, तो वैश्विक आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी पड़ सकती है और असमानताएँ और गहरी हो सकती हैं।

अंततः, मेक्सिको द्वारा लगाए गए नए शुल्क केवल एक देश या कुछ उत्पादों तक सीमित मुद्दा नहीं हैं। यह उस व्यापक बदलाव का प्रतीक हैं, जिसमें वैश्विक व्यापार व्यवस्था एक नए मोड़ पर खड़ी है। भारत सहित एशियाई देशों के लिए यह चेतावनी भी है और अवसर भी। चेतावनी इसलिए कि पुरानी रणनीतियाँ अब कारगर नहीं रहीं, और अवसर इसलिए कि आत्मनिर्भरता, विविधीकरण और दीर्घकालिक सोच के साथ आगे बढ़ने का यही सही समय है। यदि सही नीतियाँ और ठोस कदम उठाए गए, तो इस चुनौती को भविष्य की मजबूती में बदला जा सकता है।

महेन्द्र तिवारी

मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक रवि कुमार अवस्थी द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला विजय लक्ष्मी नगर परगना खैराबाद तहसील व जनपद -सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, हीवेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में छपे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोटः**-उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादो का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। R.N.I NO. UPHIN/2012/43078 मो0 नं0 -9511151254, E-Mail :- news@swatantraprabhat .com

संक्षिप्त खबरें

शरद चौधरी ने किया अधिवक्ताओ का सम्मान

बिसवां/सीतापुर क्षेत्र के विकास पुरुष शरद चौधरी ने अपने निवास अर्जुनगढ़ कदुनी में अधिवक्ताओं, पत्रकारों एवं सम्मानित नागरिकों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कदुनी क्षेत्र का विकास जनसहयोग का परिणाम है। उन्होंने बताया कि रेडिको खेतान कंपनी की स्थापना से क्षेत्र के सैकड़ों युवक-युवतियों को रोजगार मिला है तथा आगे भी विकास योजनाएं प्रस्तावित हैं। उच्च न्यायालय के अधिवक्ता राजन मिश्रा ने शरद चौधरी की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर शरद चौधरी ने बिसवां बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष आर.एन. सिंह एवं लायर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कमलेंद्र बाजपेई का माल्यार्पण कर स्वागत किया। कार्यक्रम में अधिवक्ताओं ने काव्य प्रस्तुतियों से उपस्थितजनों को मंत्रमुग्ध किया। कार्यक्रम के अंत में अधिवक्ताओं ने आयोजन के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए भविष्य में ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन की अपेक्षा जताई। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता राजकुमार वर्मा, रामेंद्र शुक्ला, बृजेश गुप्ता, रसिक बिहारी गुप्ता, नीरज श्रीवास्तव, अनिल शुक्ला सहित समाजसेवी अभिषेक अग्रवाल, उमंग राजवंशी, उत्साह राजवंशी, मुदित सिंघल, रोहित नाथ सिंह एवं कई पत्रकार उपस्थित रहे।

जिला अधिकारी डॉ0 राजा गणपति आर ने रविवार को बिसवां नगर पालिका का किया गहन निरीक्षण

बिसवां, सीतापुर जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर ने रविवार को बिसवां नगर पालिका परिषद का लगभग दो घंटे तक गहन निरीक्षण किया। इस दौरान विभिन्न पटलों की जांच की गई। निरीक्षण के समय नगर पालिका कार्यालय के नीचे फरियादियों की भारी भीड़ शिकायतें लेकर मौजूद रही। जिलाधिकारी ने हनुमत रामेश्वर दयाल इंटर कॉलेज के बगल में निर्माणाधीन अमृत सरोवर का निरीक्षण किया, जहां इंटरलॉकिंग के नीचे बजरी गायब पाई गई। इस पर डीएम ने संबंधित ठेकेदार व अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए इंटरलॉकिंग को दोबारा मानक के अनुसार बनवाने के निर्देश दिए। इसके बाद डीएम का काफिला मंसाराम मंदिर परिसर पहुंचा, जहां पड़ी पाइपलाइन को खुदवाकर मौके पर निरीक्षण किया गया। तत्पश्चात आसरा कॉलोनी, अमरनगर के समीप बने नाले का भी गहन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्थानीय नागरिकों ने नगर की विभिन्न समस्याओं से जिलाधिकारी को अवगत कराया। इस अवसर पर नगर पालिका परिषद की अधिशासी अधिकारी नीलम चौधरी सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय अविष्कार योजना के तहत क्विज व माडल प्रतियोगिताओ का आयोजन

परिषदीय विद्यालय के उच्च प्राथमिक स्तर के छात्र व छात्राओं के लिए राष्ट्रीय अविष्कार योजना के तहत क्विज व माडल प्रतियोगिताओ का आयोजन पूर्व में कराया जा चुका हैं। इन प्रतियोगिताओ के शीर्ष विजेताओं की महात्वाकांक्षी योजना एक्सपोजर विजिट हेतु ब्लाक संसाधन केंद्र सुरियावां खंड शिक्षा अधिकारी श्री यशवंत सिंह के नेतृत्व में वाराणसी शैक्षणिक भ्रमण हेतु जाया गया। इस दौरान टीएससीटी भदोही, टीएफसी वाराणसी, सारनाथ में बौद्ध पार्क, चिड़ियाघर इत्यादि स्थानों का भ्रमण कराया गया। बच्चों को नाश्ता, भोजन व किट प्रदान किया गया। बच्चों ने इस विजिट का भरपूर आनंद उठाया। इस दौरान एसआरजी विनय शंकर पांडेय, एआरपी देवेंद्र कुमार मिश्र भास्करानंद मिश्र, मनोज सिंह, सन्तोष कुमार, एलएलएफ से लालचंद, नोडल शिक्षक संकुल वेद प्रकाश, भोलानाथ सरोज, स.अ. सीताबेन सरोज, रामजी पांडेय, सभाजीत के साथ साथ 100 बच्चों सहित आदि मौजूद रहें।

सब्जी खरीदने के लिए क्रॉसिंग पर रोका टावर वैगन, 15 मिनट तक रेलवे क्रॉसिंग बंद होने से लगा जाम

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर जनपद सीतापुर में रेलवे की मनमानी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बताया जाता है कि खैराबाद क्षेत्र के टप्पा खजुरिया के समीप रेलवे क्रॉसिंग पर सब्जी खरीदने के लिए टावर वैगन को रोक दिया गया जिसके चलते रेलवे बैरियर बंद रहा। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अचानक रेलवे क्रॉसिंग पर टावर वैगन खड़ा हो गया। जिससे फाटक बंद हो गया इस दौरान न तो कोई ट्रेन गुजरने वाली थी और न ही कोई आधिकारिक सूचना दी गई। बताया जा रहा है कि इंजन में सवार रेलवे कर्मचारी सब्जी खरीदने के लिए नीचे उतर गए पास की दुकानों से सब्जी लेने लगे। इस दौरान लोग बैरियर खुलने का इंतजार करते रहे करीब 15 मिनट बाद जब रेलवे कर्मचारी सब्जी लेकर वापस टावर वैगन में सवार हुए तब जाकर टावर वैगन को आगे बढ़ाया गया। जिसके बाद रेलवे क्रॉसिंग खोला गया इस पूरी घटना से स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखी गई। कई वाहन चालकों ने रेलवे की इस लापरवाही पर सवाल उठाए कहा कि रोजाना इसी मार्ग से स्कूली बच्चे, मरीज और कामकाजी लोग गुजरते हैं जिन्हें इस तरह बेवजह रोका गया। मौके पर मौजूद लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि रेलवे क्रॉसिंग पर इंजन खड़ा है और बैरियर बंद होने के कारण दोनों ओर वाहन फंसे हुए हैं सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग रेलवे अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं जीआरपी इंस्पेक्टर अरविंद पांडे ने कहा कि उन्हें इस तरह की किसी घटना की जानकारी नहीं है वहीं, स्टेशन अधीक्षक आरके शुक्ला ने भी बताया कि उस समय ऐसी कोई ट्रेन गुजरने वाली नहीं थी मामला उनके संज्ञान में नहीं है फिलहाल वायरल वीडियो के बाद रेलवे की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं!!

ऐहार पीएचसी में मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले में 43 मरीजों का उपचार

मौसमी बीमारियों से बचाव व स्वच्छता पर किया जागरूक : डॉ. मनीष सिंह

लालगंज, रायबरेली। नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ऐहार में रविवार को आयोजित मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले में क्षेत्र के कुल 43 मरीजों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लिया। मेले के दौरान मरीजों की सामान्य जांच के साथ आवश्यक परामर्श दिया गया तथा रोगियों को निःशुल्क दवाओं का वितरण किया गया।स्वास्थ्य कर्मियों ने मरीजों को मौसमी बीमारियों से बचाव, स्वच्छता बनाए रखने और नियमित स्वास्थ्य जांच के प्रति जागरूक किया। मेले में एमबीबीएस चिकित्सक डॉ. मनीष कुमार सिंह एवं आयुष चिकित्सक ने मरीजों का परीक्षण किया। वहीं फार्मासिस्ट दिलीप कुमार ने दवाओं का वितरण किया। स्वास्थ्य केंद्र की साफ-सफाई व्यवस्था का दायित्व स्वीपर देवा नंद ने संभाला।उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत प्रत्येक रविवार को आयोजित किया जाता है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उनके निकट बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

जे पी ए की छमाही बैठक संपन्न, बैठक में संगठन के सदस्यों ने ली एकजुटता की शपथ

● पत्रकारों को मिलकर लड़नी होगी अपनी लड़ाईः विवेक प्रताप सिंह

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर क्षेत्र अंतर्गत एक निजी प्रतिष्ठान में जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एसोसियेशन (रजि0) उत्तर प्रदेश (जे पी ए) ने 14 दिसंबर रविवार को छमाही बैठक का आयोजन किया। बैठक में संगठन के विस्तार से लेकर पत्रकारों के साथ घटने वाली घटनाएं और पत्रकारों की समस्याओं तथा सामाजिक स्थिति पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में संगठन के पदाधिकारी और सदस्य गण उपस्थित रहे। संगठन के पदाधिकारी एवं वरिष्ठ पत्रकार फरहान इराकी की माता जी के आकस्मिक निधन की जानकारी पर संगठन के सभी सदस्यों द्वारा 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति की कामना की गई। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एसोसियेशन के अध्यक्ष विवेक प्रताप सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा की पत्रकारों को संगठित होकर पत्रकारों के विषय में सोचना होगा। हमें समाज की लड़ाई लड़ने के साथ-साथ अपने लिए भी समय निकालना पड़ेगा और एक दूसरे के सुख-दुख में सहभागिता करनी होगी इसके लिए हम सभी को संगठित रहना होगा। कार्यक्रम में सभी ने अपने-अपने विचार प्रस्तुत किए साथ ही जनवरी में होने वाली अगली बैठक की रूपरेखा तय की गई। बैठक में उपाध्यक्ष रवि जायसवाल, कोषाध्यक्ष नरसिंह नारायण पांडे, संरक्षक सदस्य विवेक विश्व पांडे, सचिव अभिषेक सिंह, मीडिया प्रभारी सत्येंद्र शर्मा, उपसचिव विजय शंकर दुबे, सह मीडिया प्रभारी सौरभ निगम, रंजीत सिंह, प्रवीण सिंह, जिले की टीम से कोषाध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष सनी शाह, आनंद सिंह, बबलू, रोशनी सोनकर, पूर्णिमा सोनकर, प्रियंका निगम, निशांत सिंह, शेखर सिंह, अंकित गुप्ता, विशाल कुमार, नीरज कुमार आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

डेयरी संचालक के गोली मारकर की हत्या घर में मचा कोहराम, दुकान बंद कर घर जाते समय सिर में मारी गोली

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर जनपद सीतापुर में शनिवार रात एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां बेखौफ तीन हमलावरों ने डेयरी संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, वहीं परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल शुरू कर दी है। घटना सिधौली कोतवाली क्षेत्र के महमूदाबाद चौराहे की बताई जा रही है यहां रहने वाले राहुल यादव (25) महमूदाबाद चौराहे पर काव्या डेयरी के नाम से दुकान चलाते थे शनिवार रात करीब 12 बजे राहुल रोज की तरह दुकान बंद कर बाइक से अपने घर जा रहे थे जैसे ही वह कुछ दूरी पर पहुंचे, पहले से घात लगाए हमलावर महेश, मटरू और बख्शी तालाब निवासी अभिषेक ने अचानक उन पर हमला कर दिया आरोपी ने बेहद नजदीक से राहुल के सिर में गोली मार दी, जिससे वह मौके पर ही गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े। गोली लगने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके की ओर दौड़े। स्थानीय लोगों की मदद से राहुल को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) सिधौली ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया। लखनऊ के अस्पताल में इलाज के दौरान रविवार सुबह राहुल यादव ने दम तोड़ दिया। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और गांव व इलाके में शोक की लहर दौड़ गई परिजन हत्या के पीछे पुरानी रंजिश की आशंका जता रहे हैं सूचना मिलने पर सिधौली कोतवाली पुलिस के साथ ही उच्चाधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है एएसपी दक्षिणी दुर्गेश सिंह ने बताया कि हत्या के कारणों की गहनता से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा!!

40 रिक्त ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक/एकाउन्टेंट-कम-डाटा इण्ट्री आपरेटर के चयन हेतु करें आवेदनः डीपीआरओ

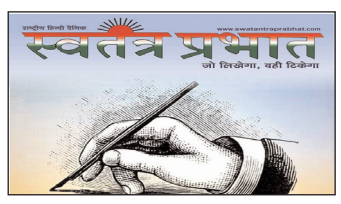

रायबरेली, जिला पंचायत राज अधिकारी सौम्य शील सिंह ने बताया है कि शासनादेश में निहित प्राविधानानुसार जनपद की 40 रिक्त ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक/एकाउन्टेंट-कम-डाटा इण्ट्री आपरेटर के चयन हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। वांछित अहर्ता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी अपना आवेदन 15 दिसम्बर 2025 से 29 दिसम्बर 2025 तक कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी/विकास खण्ड कार्यालय/ग्राम पंचायत कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके सम्बन्ध में किसी भी विधिक जानकारी/सहायता हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालयों में किसी भी कार्यदिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।

अजय कुमार सिंह को अमिटी विश्वविद्यालय से नैनो टेक्नोलॉजी के उन्नत अनुप्रयोगों पर पीएचडी की उपाधि

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता एर. अजय कुमार सिंह को अमिटी विश्वविद्यालय द्वारा सड़क निर्माण में नैनो टेक्नोलॉजी के उन्नत अनुप्रयोग (Advanced Applications of Nano Technology in Road Construction) विषय पर पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। यह शोध कार्य आधुनिक सड़क निर्माण इंजीनियरिंग में नैनो तकनीक के व्यावहारिक, तकनीकी तथा आर्थिक उपयोगों पर केंद्रित है। इस शोध विषय का चयन प्रो. (डॉ.) भरत राज सिंह, महानिदेशक (तकनीकी), स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, लखनऊ द्वारा किया गया, जिन्होंने इस शोध में को-सुपरवाइज़र की भूमिका निभाई। अमिटी विश्वविद्यालय की ओर से प्रो. आशिता कुलश्रेष्ठ एवं डॉ. अनिरुद्ध बनर्जी ने क्रमशः सुपरवाइज़र एवं को-सुपरवाइज़र के रूप में मार्गदर्शन प्रदान किया। शोध कार्य में सड़क निर्माण इंजीनियरिंग में नैनो सामग्री जो अभी तक लागू नहीं हो रहा है, के उन्नत अनुप्रयोगों का विस्तार से विश्लेषण किया गया है। कंक्रीट की बेहतर मजबूती एवं टिकाऊपन प्राप्त करने हेतु नैनो सामग्री की आर्थिक रूप से उपयुक्त मात्रा (Economical Proportion) निर्धारित करने के लिए विस्तृत गणनाएँ प्रस्तुत की गई हैं। इससे लागत में वृद्धि किए बिना संरचनात्मक क्षमता बढ़ाने की संभावनाएँ स्पष्ट होती हैं। इसके अतिरिक्त, प्रबलित कंक्रीट (RC) संरचनाओं में स्टील रीबार में होने वाले क्षरण (Corrosion) का पता लगाने हेतु एक नवीन तकनीक प्रस्तुत की गई है। इसमें क्रिस्टल आधारित डिस्प्लेसमेंट सेंसर्स का उपयोग दर्शाया गया है। शोध में एक उन्नत डबल-डिफेक्ट लेयर्ड vD क्वाटरनरी फोटोनिक क्रिस्टल संरचना भी प्रस्तावित की गई है, जो संरचनात्मक स्वास्थ्य निगरानी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान मानी जा रही है। यह शोध सड़क एवं अवसंरचना विकास के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी के व्यावहारिक एवं भविष्यपरक उपयोगों की दिशा में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।

जीआरपी के जवानों ने बुजुर्ग की बचाई जान, रेलवे ट्रैक पर ट्रेन आने से पहले पटरी से हटाया

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर जनपद सीतापुर में रेलवे जंक्शन पर जीआरपी के जवानों की तत्परता और साहस से एक बुजुर्ग व्यक्ति की जान बच गई। यह घटना उस समय हुई जब एक बुजुर्ग रेलवे स्टेशन पर लापरवाही से रेलवे लाइन पार कर रहे थे और उसी दौरान ट्रेन प्लेटफॉर्म की ओर आ रही थी इसी दौरान प्लेटफॉर्म पर मौके पर तैनात जीआरपी के जवानों ने बिना समय गंवाए साहसिक कदम उठाया जानकारी के अनुसार, थाना जीआरपी में तैनात हेड कांस्टेबल राकेश कुमार खरवार और हेड कांस्टेबल रजनीश कुमार ने बुजुर्ग को ट्रेन की चपेट में आते देख तुरंत दौड़ लगाई दोनों जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना बुजुर्ग को रेलवे ट्रैक से खींचकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया कुछ ही पलों बाद ट्रेन उसी ट्रैक से गुजर गई अगर जवानों ने पल भर की भी देरी की होती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। इस पूरी घटना का वीडियो स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह दोनों जीआरपी जवान बुजुर्ग को बचाने के लिए दौड़ते हैं और समय रहते उसे सुरक्षित कर लेते हैं जवानों की इस फुर्ती और सूझबूझ की चारों ओर सराहना हो रही है। घटना के बाद बुजुर्ग व्यक्ति काफी घबराए हुए नजर आए, जिन्हें बाद में समझाकर सुरक्षित स्थान पर बैठाया गया रेलवे प्रशासन और यात्रियों ने जीआरपी जवानों के इस साहसिक कार्य की प्रशंसा की है लोगों का कहना है कि ऐसे जांबाज पुलिसकर्मियों की वजह से ही रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाती है। जीआरपी अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों को स्वयं भी सतर्क रहने की जरूरत है और रेलवे लाइन पार करने के लिए निर्धारित रास्तों का ही उपयोग करना चाहिए!!

आर्यकुल कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड रिसर्च, सीतापुर में नवप्रवेशित विद्यार्थियों के स्वागत हेतु फ्रेशर्स पार्टी का किया गया आयोजन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर आर्यकुल कॉलेज आफ फार्मेसी एंड रिसर्च सीतापुर में नव प्रवेशित विद्यार्थियों के स्वागत हेतु फ्रेशर्स पार्टी आर्य शुभा 2025' का भव्य एवं हर्षोल्लासपूर्ण आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ-साथ मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित कर उनके उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन की सराहना की गई। कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताओं के अंतर्गत धर्मेन्द्र को मिस्टर आर्य-शुभा, अपराजिता को मिस आर्य-शुभा, अनुराग को मिस्टर एलिगेंट, क्षमा को मिस एलिगेंट, शुभम को मिस्टर टैलेंट तथा शैलेन्द्री को मिस टैलेंट का खिताब प्रदान किया गया।

इसके साथ ही शैक्षणिक सत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। बी.फार्म छठे सेमेस्टर में प्रथम स्थान रश्मि, द्वितीय स्थान मुदस्सिरा एवं तृतीय स्थान नीरज को प्राप्त हुआ। बी.फार्म चतुर्थ सेमेस्टर में प्रथम स्थान रोली, द्वितीय स्थान अरमान तथा तृतीय स्थान कामरान रहे। बी.फार्म द्वितीय सेमेस्टर में प्रथम स्थान तनवीर, द्वितीय स्थान अरबिया एवं तृतीय स्थान सोनिका भारती ने प्राप्त किया। वहीं डी.फार्म प्रथम वर्ष में प्रथम स्थान तुफैल एवं मो. जाफर, द्वितीय स्थान अनुराग एवं कौशलेंद्र तथा तृतीय स्थान शुधांशु एवं अबू सहामा को संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कॉलेज के प्रबन्ध निदेशक डॉ. सशक्त सिंह ने विद्यार्थियों को मेहनत, अनुशासन एवं सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। डीन एकेडमिक श्रीमती रुचि सिंह ने कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों के आत्मविश्वास और प्रतिभा को निखारते हैं। प्राचार्या डॉ. स्तुति वर्मा ने विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर परिश्रम करने का संदेश दिया।

अंत में अतिथियों द्वारा विजेताओं एवं मेधावी विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए तथा सफल आयोजन के लिए आयोजन समिति की सराहना करते हुए विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। इस कार्यक्रम में कॉलेज के प्रबन्ध निदेशक डॉ. सशक्त सिंह, संकाय प्राचार्या डॉ. स्तुति वर्मा, डीन एकेडमिक श्रीमती रुचि सिंह , उपनिदेशक डॉ. आदित्य सिंह, डॉ. अब्दुल रब खान, रजिस्ट्रार रोहित सिंह, अध्यापक राजीव कुमार, ऋषभ शुक्ल, तबस्सुम बानो, अनुभा धुरिया, रेहान , अभिमन्यु, तान्या उपाध्याय, नीलम वर्मा , प्रांजुल वर्मा, मोहित यादव, साहिल सिंह , तिलक राज , अरुण सिंह, प्रीति यादव, प्रीति तिवारी, प्रवीण , अबरार, रमा सिंह आदि लोग मौजूद रहे।

अखिल भारतीय हिंदू महासभा में संगठन विस्तार,अनूप अग्रवाल बने प्रदेश उपाध्यक्ष मुख्य मोर्चा

● अनूप अग्रवाल के मनोनयन से संगठन को नई दिशा एवं नई ऊर्जा प्राप्त होगी- प्रदेश अध्यक्ष

मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी गई है,उसका पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निर्वहन करुंगा- अनूप अग्रवाल

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

रायबरेली। अखिल भारतीय हिंदू महासभा उत्तर प्रदेश इकाई में संगठनात्मक विस्तार के क्रम में शनिवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रख्यात समाजसेवी शैलेंद्र अग्निहोत्री ने संगठन को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में कदम उठाते हुए अनूप अग्रवाल को प्रदेश उपाध्यक्ष,मुख्य मोर्चा (उत्तर प्रदेश) के पद पर मनोनीत किया।इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र अग्निहोत्री ने कहा कि अनूप अग्रवाल का मनोनयन संगठन की हिंदू हितैषी विचारधारा,राष्ट्र निर्माण एवं समाज सेवा के उद्देश्यों के अनुरूप किया गया है। उन्होंने कहा कि श्री अग्रवाल लंबे समय से सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे हैं और युवाओं को संगठित करने की क्षमता रखते हैं।उनके मनोनयन से संगठन को गौ रक्षा,राष्ट्र धर्म,सामाजिक समरसता और सेवा भाव के क्षेत्र में नई दिशा एवं नई ऊर्जा प्राप्त होगी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें न केवल आशा बल्कि पूर्ण विश्वास है कि अनूप अग्रवाल अपने दायित्वों का निष्ठा,ईमानदारी और सक्रियता के साथ निर्वहन करते हुए संगठन को प्रदेश स्तर पर मजबूती प्रदान करेंगे तथा युवाओं को राष्ट्र सेवा से जोड़ने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे।वहीं,अनूप अग्रवाल ने संगठन के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है,उसका वे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि वे युवाओं को संगठन से जोड़कर हिंदू समाज के हित,गौ संरक्षण और राष्ट्र सेवा के लिए निरंतर कार्य करेंगे।अनूप अग्रवाल के प्रदेश उपाध्यक्ष मुख्य मोर्चा पद पर मनोनयन की

घोषणा होते ही अखिल भारतीय हिंदू महासभा के रायबरेली जिला संगठन में उत्साह का माहौल बन गया।जिला अध्यक्ष विवेक मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष राजेश सिंह, जिला संरक्षक महेंद्र अग्रवाल, प्रदेश संयोजक राजेंद्र अवस्थी, विधिक सलाहकार राजेश श्रीवास्तव, अमन अग्रवाल, शैलेंद्र सिंह, गंगेश चौरसिया, प्रवेश सिंह जिला महासचिव सहित संगठन के समस्त पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी और संगठन के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। संगठन के पदाधिकारियों ने विश्वास जताया कि अनूप अग्रवाल के नेतृत्व में हिंदू महासभा प्रदेश में सक्रिय भूमिका निभाएगा और संगठन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का कार्य करेगा।

पार्श्वनाथ भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव पर जैन मंदिर में हुआ धार्मिक आयोजन

भदोही। रविवार को श्री पार्श्वनाथ भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव के अवसर पर जैन मंदिर में भक्ति एवं श्रद्धा के साथ विशेष धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रातः काल से ही मंदिर परिसर में जैन समाज के लोगों की भारी उपस्थिति रही और पूरे वातावरण में आस्था व उत्साह का संचार दिखाई दिया। इस अवसर पर सत्रह भेदी पूजा का सामूहिक आयोजन किया गया, जिसमें पुरुषों एवं महिलाओं ने विधिविधान से पूजा-अर्चना कर भजन-कीर्तन गाए। सुबह 11 बजे पंच कल्याणक पूजा संपन्न हुई, जिसके पश्चात स्वधर्मी वात्सल्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के अंत में श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद वितरण किया गया। जैन समाज के लोगों ने एक-दूसरे को जन्म कल्याणक महोत्सव की शुभकामनाएं दीं और अधिक से अधिक संख्या में समय पर पहुंचकर पुण्य लाभ लेने का अनुरोध किया। पूरे आयोजन के दौरान जैन समाज के लोगों में हर्ष, उल्लास और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला।

मऊ गांव में पंचमुखी प्राचीन हनुमान मंदिर के सौंदर्यीकरण का चल रहा कार्य

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

महराजगंज/रायबरेली: क्षेत्र के पूरे अहलादी मजरे मऊ गांव में इन दिनो श्री पंचमुखी प्राचीन हनुमान मंदिर के सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा था। सौंदर्यीकरण का कार्य पूर्व प्रमुख सत्येन्द्र प्रताप सिंह के प्रयास से सरकारी व व्यक्तिगत सहयोग से किया गया था। इसमें बाउंड्री वॉल, मंदिर की छत, गेट और इंटरलॉकिंग का निर्माण शामिल है। अब रंग रोगन व मंदिर के अन्य कार्यो के लिए स्थानीय लोगों ने क्षेत्रीय लोगों से फेसबुक वॉल पर एक पोस्ट करके सहयोग की अपील करी है।

आपको बता दें कि, थाना क्षेत्र के मऊ गांव निवासी पूर्व प्रमुख सत्येंद्र प्रताप सिंह के प्रयासों से व्यक्तिगत और सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत गांव के पूरे अहलादी स्थित प्राचीन पंचमुखी हनुमान मंदिर को भव्य रूप में तैयार किया जा चुका है। मंदिर में मूर्ति सुंदरीकरण, प्लास्टर और रंग-रोगन का कार्य शेष है। इसके लिए क्षेत्र के भामाशाहों से दान की अपील करी गई है। स्थानीय लोगों का मत है कि, मंदिर निर्माण में सभी लोगों के श्रद्धानुसार सहयोग की आवश्यकता होती है, इसीलिए मंदिर के सौंदर्यीकरण में श्रद्धालुओ से दान स्वरूप भेंट का उपयोग मंदिर को दिव्य और भव्य बनाने में किया जाएगा।

सनातन परंपरा के अनुसार दान स्वरूप प्राप्त भेंट से श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर का शेष सौंदर्यीकरण का कार्य पूरा कराया जाएगा। दान स्वरूप सहयोग के लिए फेसबुक वॉलपेपर एक स्थानीय व्यक्ति द्वारा पोस्ट करके सहयोग की अपील करी गई है। अंत में यह भी लिखा हुआ है कि, फेसबुक के माध्यम से कमेंट करके क्षेत्र के दानदाता अथवा भामाशाहों द्वारा किया गया छोटा सा प्रयास मंदिर को दिव्य और भव्य बनाने के लिए काफी होगा। दान की पारदर्शिता के लिए फेसबुक वॉलपेपर पर यह भी कहा गया है कि, जब खर्च की धनराशि पूरी हो जाएगी, तो लोगों के सहयोग से लगने वाला सामान कमेंट के ही माध्यम से मंदिर प्रांगण में मंगवा लिया जाएगा, ताकि सुगमता से पंचमुखी हनुमान मंदिर को दिव्या और भव्य बनाया जा सके।

इसके अलावा मंदिर प्रांगण में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी आगामी मंगलवार को विशाल मेले का आयोजन किया गया है, जिसके लिए कमेटी के सदस्यों द्वारा सोमवार को श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ एवं मंगलवार को पूर्ण आहुति के बाद विद्वान पंडितो द्वारा हवन यज्ञ, कन्या भोज एवं विशाल मेले का आयोजन होगा। रात में रंगारंग प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया है। मेला कमेटी द्वारा क्षेत्रीय लोगों को मेले को भव्य बनाने के लिए आमंत्रित किया गया है।

संक्षिप्त खबरें

तेज रफ्तार मौरंग ट्रक की टक्कर से युवक की मौत, साथी घायल

हमीरपुर- राठ क्षेत्र के चिकासी थाना अंतर्गत मंगरौठ मोड़ के आगे हुए सड़क हादसे में 20 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका साथी घायल हो गया। हादसा उस समय हुआ, जब तेज रफ्तार बालू से भरे ट्रक ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। मृतक की पहचान बंगरा गांव निवासी कपिल (20) पुत्र रामशरण के रूप में हुई है। वह अपने चचेरे भाई संदीप के साथ जालौन जनपद के जैसारी गांव में क्रिकेट मैच खेलकर अपने गांव बंगरा लौट रहा था। रास्ते में मंगरौठ मोड़ के आगे अचानक बालू से भरे ट्रक ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक चला रहा कपिल गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे तत्काल गोहांड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और गांव में शोक की लहर दौड़ गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। स्थानीय लोगों ने ट्रक चालक को मौके पर ही पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। परिजनों के अनुसार कपिल अविवाहित था और पढ़ाई कर रहा था। उसके परिवार में मां शिवकली, बहन संध्या और भाई सुनील सहित अन्य सदस्य हैं। चिकासी थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

कोहरे में दो डंपरों की आमने-सामने टक्कर, चालक गंभीर घायल

हमीरपुर- सुमेरपुर थाना क्षेत्र के कुंडौरा गांव के पास हाईवे पर रविवार तड़के कोहरे के कारण दो डंपरों की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में एक डंपर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद कानपुर रेफर किया गया है। घटना रविवार सुबह करीब छह बजे ओम हरिहर महाविद्यालय के समीप हुई। जानकारी के अनुसार, एक डंपर कबरई से कानपुर की ओर जा रहा था, जबकि दूसरा डंपर हमीरपुर से महोबा की दिशा में आ रहा था। घने कोहरे के चलते दोनों वाहन एक-दूसरे से टकरा गए। कानपुर की ओर जा रहे डंपर का चालक मोहम्मद यासीन (निवासी प्रतापगढ़) टक्कर के बाद केबिन में फंस गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद चालक को केबिन से बाहर निकाला। घायल चालक को एंबुलेंस से सदर अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए कानपुर रेफर कर दिया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात सुचारु कराया और मामले की जांच शुरू कर दी है।

चलते ट्रक में लगी आग, चालक ने कूदकर बचाई जान

हमीरपुर- शनिवार रात नेशनल हाईवे-34 पर उस समय हड़कंप मच गया, जब एक चलते ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक के केबिन से धुआं उठता देख चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए वाहन को सड़क किनारे खड़ा कर दिया और तुरंत कूदकर अपनी जान बचाई। कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरा ट्रक धू-धू कर जलने लगा। यह घटना सुमेरपुर थाना क्षेत्र में जेके सीमेंट फैक्ट्री से कुछ दूरी पर हुई। जानकारी के अनुसार, ट्रक हमीरपुर में सीमेंट उतारने के बाद वापस जेके सीमेंट फैक्ट्री लौट रहा था। फैक्ट्री पहुंचने से पहले ही ट्रक में शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे केबिन के अंदर से धुआं निकलने लगा और आग भड़क उठी। ट्रक चालक शिवशंकर निषाद, निवासी पपरेंदा जनपद बांदा ने बताया कि धुआं दिखाई देने पर उसने तुरंत ट्रक को हाईवे किनारे रोक दिया और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग तेजी से फैलती चली गई। स्थिति बिगड़ती देख उसने बिना देर किए फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि, तब तक ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो चुका था। इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को सामान्य कराया। लगातार हो रही वाहन आग की घटनाओं से चालकों को सतर्क रहने की अपील की है।

ग्राम पंचायत करकटी में लग रहे फर्जी बिल अधिकारी की साठ गाठ से सचिव की बल्ले बल्ले

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

शहडोल। जिले के जनपद पंचायत सोहागपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत करकटी में भ्रष्टाचार चरम पर हैं। आप को बात दे कि ग्राम पंचायत में लगातार एक से बढ़ कर एक फर्जी बिल लगाया जा रहा है। लाख विरोध के बाद और अखबारों की सुर्खियों में चर्चित सचिव का क्या है कहानी आइए एक ओर जानने का प्रयास करते हैं। आपको बता दे कि सचिव खोजवा चर्मकार की कहानी 2014 से शुरू होती हैं जब से ग्राम पंचायत करकटी में आये और एक से बढ़ कर एक कामों को अपने सिस्टम में दबाया और खूब मजे लुटे उस समय भी ग्रामीणों के भारी विरोध के बाद सचिव के जुगाड़ के आगे ग्रामीणों की एक न चली। जहाँ एक ओर सरकार हर व्यक्ति को हर सम्भव योजना के साथ साथ व्यक्ति विशेष को लाभान्वित करने का संकल्प लिया हैं। वही पंचायत सचिव के द्वारा सभी बिलों को छोटे छोटे अमाउंट में पंचायत दर्पण सहित अन्य पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। जिससे यह साफ हो रहा कि भ्रष्टाचार किस कदर सचिव सरपंच के द्वारा मचा रखा हैं। प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य के लिए लाखों रुपए मुहैया करा रही है। जिससे ग्रामीण स्तर पर उपयोगी व सभी कार्य गुडवत्ता पूर्ण हो सके। जिससे ग्रामीणों को सुविधा मुहैया और जरूरत पूरी की जा सकें। जिसके तहत पंचायत स्तर पर शासन द्वारा चलाए गए कई योजनाएं जो ग्रामीण हित के लिए कराई जाती है, पर इस कालाबाजारी के दौर पर और मिलावट खोरी के इस दौर में हर कोई सिर्फ अपने कमिशन से मतलब रखता है। उसे निर्माण कार्य से कोई भी मतलब नहीं रहता। फिर चाहे वह किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य क्यों ना

हो, कारण यह भी हैं कि अधिकारी जमीनी स्तर पर मौका मुआयना करने नहीं जाते। जिससे कि निर्माण एजेंसी और अधिकारियों की साठ-गाठ से निर्माण धीन कार्य भी अधूरा और ढहने की कगार पर हैं।

हमीरपुर में सड़क हादसे में तीन व्यक्तियों की मौत, चार अन्य घायल

हमीरपुर जिले के मौदहा थाना क्षेत्र में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर रविवार को एक तेज रफ्तार बस की टक्कर से एसयूबी कार सवार तीन व्यक्तियों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, महोबा जिले के खन्ना थाना क्षेत्र के गौएड़ी गांव निवासी सिद्धांगोपाल (65), रामसहोदर (40) और उनके बड़े भाई घनश्याम (55) चार अन्य लोगों के साथ एक महिला की अस्थिया लेकर एसयूवी कार से प्रयागराज जा रहे थे, तभी पीछे से आ रही तेज रफ़्तार बस ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि टक्कर इतनी तेज थी कि मौके पर ही तीनों की मौत हो गयी और अन्य चारों गंभीर रूप से घायल हो गए। मौदहा कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक संतोष सिंह ने बताया कि तीनो शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें मेडिकल कॉलेज बांदा भेज दिया गया है।

सोहागपुर कालरी क्षेत्र के समस्त ठेका कंपनियों में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाए-अभिषेक वर्मा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

शहडोल धनपुरी- नवनिर्वाचित युवक कांग्रेस के जैतपुर विधानसभा अध्यक्ष अभिषेक वर्मा ने क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर एसईसीएल के अंतर्गत सोहागपुर क्षेत्र में समस्त ठेका कंपनी में शिक्षित युवा वर्ग के लिए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक युवा कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल सोहागपुर क्षेत्र के महाप्रबंधक से मिलकर चर्चा करेगा। अगर सार्थक चर्चा हुई तो आगे कोई आंदोलन नहीं होगा। नहीं तो युवक कांग्रेस आंदोलन के लिए बाध्य होगा। एसईसीएल सोहापुर क्षेत्र के अंतर्गत समस्त ठेका कंपनी के द्वारा जिस तरह से शिक्षित युवा वर्ग को उपेक्षित करते हुए बाहरी लोगों को प्राथमिकता दे रही है। इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे जबकि क्षेत्र के युवाओं के पास भरपूर काबिलियत के साथ डिग्री डिप्लोमा पूर्ण करने के बाद भी दर-दर को भटकते रहते हैं। स्थानीय शिक्षित बेरोजगारों के साथ एक लंबे समय से उपेक्षाएं की जा रही है। जिसके लिए अब युवक कांग्रेस के जैतपुर विधानसभा अध्यक्ष अभिषेक वर्मा के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जाएगी और इसमें एक निर्णायक स्थित तक ले जाने की पूर्ण कोशिश की जाएगी। इसके लिए जिस तरह की भी आंदोलन किया जाना पड़ेगा। उसके लिए युवक कांग्रेस स्थानीय शिक्षित युवा वर्ग के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने के तत्पर है।

श्रीभूमि जिले के आर्दश कृष्णनगर गाँव विकास के लाभ से वंचित

● सिर्फ नाम में आदर्श! आवश्यक सुविधाओं में पूरी तरह असफल!

भारत के प्रधानमंत्री और असम के मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

श्रीभूमि- वर्तमान सरकार 'सबका साथ सबका विकास' सबका विश्वास इस नारे के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकासात्मक कार्यों के जरिए आर्दश ग्राम योजना के तहत विभिन्न परियोजनाओं में करोड़ों रुपये का आवंटन कर रही है। ताकि आम लोगों को समग्र विकास की इन परियोजनाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का पानी, स्वच्छता, बुनियादी ढांचा और सामाजिक विकास (जैसे मॉडल आंगनवाड़ी स्कूल, उप-स्वास्थ्य केंद्र, शौचालय, बिजली, सड़क और सामुदायिक केंद्र के बड़े हॉल को ऑडिटोरियम आदि के लिए सरकारी फंड और केंद्रीय-राज्य परियोजनाओं का समन्वय किया जाता है। इन परियोजनाओं के माध्यम से जनता की समस्याओं का समाधान किया जाता है। लेकिन असम श्रीभूमि जिले के रामकृष्णनगर विधानसभा क्षेत्र के दरगारबंद जीपी का आदर्श कृष्णनगर गाँव विकास के मामले में केवल नाम में ही मॉडल विलेज है, वास्तव में यह अत्यंत बदहाल स्थिति में है। कृष्णनगर गाँव के विकास की बात करें तो सड़क की स्थिति खराब है, पीने के पानी के प्रबंध के लिए [illegible] की स्थापना हेतु सर्वेक्षण किया गया था, लेकिन आज तक जल जीवन मिशन के अंतर्गत कोई परियोजना नहीं है और पानी की सुविधा भी इस योजना से वंचित है। गाँववासियों को स्वच्छता, बुनियादी ढांचा और सामाजिक विकास (जैसे उच्च गुणवत्ता वाला उप-स्वास्थ्य केंद्र, शौचालय, स्कूलों तक पहुँचने के लिए सड़क, कम्युनिटी हॉल के बड़े हॉल या ऑडिटोरियम हॉल) की कोई सुव्यवस्था नहीं है। आम लोगों को अत्यधिक कष्ट सहना पड़ रहा है, बावजूद इसके केवल विकास और विकास के वादों का ही जिक्र होता है और विकास की कोई खबर नहीं है। आर्दश कृष्णनगर गाँव की सड़क की खराब हालत के बाद पिछले वर्ष सड़क निर्माण के लिए लाल मिट्टी से भराई का काम विभागीय अधिकारी एवं ठेकेदार की देखरेख में शुरू किया गया। भले ही मिट्टी की भराई का काम पूरा हो गया हो, लेकिन आजतक इस काम से संबंधित कोई जानकारी का बोर्ड नहीं देखा गया और यह भी नहीं पता कि किस परियोजना के तहत मिट्टी भरी गई, गाँव का आम आदमी इस विषय में अनजान है। लेकिन इस सड़क निर्माण कार्य में केवल मिट्टी भराई का काम हुआ, मिट्टी के ऊपर पत्थर या सीसी ब्लॉक स्थापित नहीं किए गए। रास्ते का काम आज तक अधूरा है और गाँव के लोगों के अनेक सवाल हैं कि यह रास्ता कब पूरा होगा। लाल मिट्टी डालने के बाद बारिश के मौसम में दिन में चलने में विभिन्न तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कच्ची मिट्टी वाले रास्ते में। गाँव की इस कठिन स्थिति में ग्रामीणों को चलना पड़ता है। जनप्रतिनिधियों द्वारा गाँव का निरीक्षण करने के बाद केवल आश्वासन और आश्वासनों की झड़ी मिलती है। इस सर्दियों के मौसम में अगर यह रास्ता नहीं बनता है तो अगले वर्षा मौसम में स्थिति खराब होने में देर नहीं लगेगी। केवल इस रास्ते से वाहन चालक और दैनिक यात्री अत्यधिक परेशानियों का सामना करेंगे। इसी रास्ते पर रोज़मर्रा के लोग, स्कूल के छात्र और रोगी चलना पड़ते हैं क्योंकि कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। परिणामस्वरूप, हर दिन ग्रामीण इस लाल मिट्टी वाले खराब रास्ते के कारण विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गाँव के लोगों के चलने का एकमात्र रास्ता इस गाँव का ही है और मिट्टी भराई के काम की सही जांच, सूचना बोर्ड लगाना और अगले वर्षा मौसम से पहले रास्ता सुधारने की मांग आम लोग करते हैं। इस बीच हाल ही में भारी

वर्षा के कारण सिंगला नदी के जल प्रवाह में आदर्श कृष्णनगर गाँव की सिंगला नदी का प्रभाव के कारण पूरे गांव की एकमात्र सड़क के विभिन्न हिस्सों में गाड या प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी है क्योंकि यह सड़क सिंगला नदी के बहुत करीब है और खतरनाक स्थिति में है, कई घर और गांव के लोग डर और आतंक में रहते हैं। हालांकि लंबे समय से इस ग्रामीण सड़क के उन हिस्सों में सरकारी तौर पर नदी के कटाव से संरक्षण गाड बनाने की मांग की गई थी। मांग के मुताबिक नेताओं का वादा था कि प्रोटेक्शन गाड दिया जाएगा, लेकिन आज तक केवल वादा ही वादा है। अगर गाड नहीं दिए गए और जल्द ही यह ठीक नहीं किया गया, तो स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी, फिर जगह नरम हो जाएगी और सिंगला नदी के जल प्रवाह में सड़क बह जाएगी, स्थानीय लोग ने कहा कि गांव के लोगों के आवागमन की एकमात्र सड़क की मरम्मत के साथ-साथ आदर्श गांव बनने के लिए क्या-क्या आवश्यक है, इस पर ध्यान देकर कदम उठाए जाएं तो विभिन्न समस्याओं का समाधान होगा और लोगों के कल्याण में मदद मिलेगी। ताकि इस मामले में विधिक कदम उठाकर पूरे आदर्श कृष्णनगर गांव की सड़क को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में नए तरीके से परियोजना के माध्यम से नदी के कटाव वाले हिस्सों की पहचान करके प्रोटेक्शन गाड देकर सुरक्षित किया जा सके। इसलिए ईस बिषय पर भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया। ताकि जल्द से जल्द समस्या का समाधान हो सके।

सुनील रैदास बने वरदान फाउंडेशन शहडोल जिला के जिलाध्यक्ष

● समाजसेवा, सड़क सुरक्षा और जन-जागरूकता अभियानों को मिलेगी नई दिशा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

शहडोल। समाजसेवा के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय वर्दान फाउंडेशन ने संगठन को जिला स्तर पर और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। फाउंडेशन की केंद्रीय समिति द्वारा श्री सुनील रैदास को जिला अध्यक्ष (शहडोल) के पद पर नियुक्त किया गया है। इस आशय का औपचारिक मनोनयन पत्र दिनांक 11 दिसंबर 2025 को जारी किया गया।

मनोनयन पत्र पर मध्य प्रदेश अध्यक्ष कैलाश कुमार अहिरवार एवं महासचिव कृष्णा शर्मा के हस्ताक्षर हैं। पत्र में उल्लेख किया गया है कि श्री रैदास की सामाजिक सक्रियता, संगठन के प्रति निष्ठा, कार्यकुशलता तथा जनहित से जुड़े मुद्दों पर उनकी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है।

फाउंडेशन द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि नवनियुक्त जिला अध्यक्ष सुनील रैदास को शहडोल जिले में संगठन की गतिविधियों को व्यापक स्तर पर विस्तार देने की जिम्मेदारी दी गई है। उनके प्रमुख दायित्वों में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान, हेलमेट व सीट बेल्ट के उपयोग को बढ़ावा देना, यातायात नियमों के पालन हेतु जन-जागरूकता, नशा मुक्ति अभियान, चिकित्सा सहायता एवं सामाजिक कल्याण योजनाओं का प्रचार-प्रसार, सदस्यता अभियान तथा जिला एवं ब्लॉक स्तर पर संगठनात्मक इकाइयों का गठन शामिल रहेगा।

मनोनयन पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि श्री रैदास का कार्यकाल प्रारंभिक रूप से एक वर्ष का रहेगा, जिसे संगठन द्वारा समय-समय पर किए जाने वाले कार्य मूल्यांकन के आधार पर आगे बढ़ाया जा सकेगा। संगठन को विश्वास है कि उनके नेतृत्व में शहडोल जिले में वर्दान फाउंडेशन की गतिविधियाँ और अधिक प्रभावी होंगी तथा समाजसेवा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस अवसर पर

श्री सुनील रैदास ने केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे संगठन द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाएंगे। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि वर्दान फाउंडेशन की जनहितकारी योजनाएँ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे।

उल्लेखनीय है कि वर्दान फाउंडेशन लंबे समय से देशभर में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, यातायात सुरक्षा, स्वास्थ्य जागरूकता एवं सामाजिक सरोकारों से जुड़े अभियानों के माध्यम से सक्रिय भूमिका निभाता आ रहा है। सुनील रैदास की नियुक्ति को शहडोल जिले में संगठन को नई ऊर्जा और गति देने वाला कदम माना जा रहा है।

किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने की पांच गांवों की पंचायत

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

हमीरपुर- रविवार सुबह लगभग ग्यारह बजे मौदहा तहसील क्षेत्र के न्यूरिया गांव के काली माई मंदिर परिसर में भारतीय किसान यूनियन द्वारा पांच गांव के किसानों की पंचायत आयोजित के गई , जिसमें सैकड़ो किसानों ने भाग लिया ।किसानों की समस्याओं को लेकर आयोजित पंचचायत में जंगली गोवंश ,प्राइवेट खाद विक्रेताओं द्वारा किसानों से ज्यादा मूल्य लेना व सहकारी समितियों के सचिव द्वारा खाद में गलत व्यवहार करने आदि से संबंधित चर्चा छाई रहीं। बताते चलें कि हाल ही में जिलाधिकारी व जिला मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के आदेशानुसार उप जिलाधिकारी मौदहा को भूमि चिन्हांकन हेतु पत्र जारी किया गया था ,लेकिन अभी तक गोवंश संरक्षण हेतु भूमि का चयन नहीं किया गया है। पंचायत में तय किया गया कि किसानों की समस्याओं के निस्तारण हेतु सोमवार उपजिलाधिकारी मौदहा को भारतीय किसान यूनियन द्वारा ज्ञापन दिया जाएगा।इसके बावजूद भी समय रहते अगर किसानों की समस्याओं का निस्तारण नहीं होता तो भारतीय किसान यूनियन मौदहा तहसील परिसर में प्रदर्शन और आंदोलन करेगी।पंचचायत में भाकियू के जिला अध्यक्ष शिवपूजन निषाद, जिला कोषाध्यक्ष रज्जू प्रसाद कुशवाहा, जिला उपाध्यक्ष संतराम फौजी,जिला सचिव रामपाल कुशवाहा, मीडिया प्रभारी पारस सैनी, तहसील अध्यक्ष मौदहा शिवकरण मिश्रा, ब्लॉक अध्यक्ष मौदहा बलबीर वर्मा, तहसील उपाध्यक्ष रामावतार कुशवाहा, तथा युवा जिला अध्यक्ष अरविंद गोस्वामी, ग्राम अध्यक्ष न्यूरिया, श्रीचंद प्रजापति, नाथूराम प्रजापति मास्टर साहब न्यूरिया, ग्राम प्रधान श्री कन्हैया द्विवेदी, तथा मुन्नालाल कुशवाहा, जयनारायण तिवारी आदि तमाम किसानों ने हिस्सा लिया।

श्रीभूमि जिले के काज़ीरबाजार पोलढहर गाँव पंचायत में बिना रिश्वत के आवास नहीं मिल रहा

PMAY आवास के नाम पर घोटाले का आरोप, प्रभावित व्यक्ति।

श्रीभूमि- श्रीभूमि जिले के पाथारकांडी विकास खंड के अंतर्गत काज़ीरबाजार पलढहर गाँव पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) सहित कई ग्रामीण विकास परियोजनाओं में व्यापक भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। दिन-ब-दिन बढ़ते आरोपों ने पूरे क्षेत्र में भारी हलचल पैदा कर दी है। हाल ही में, वार्ड नंबर 4 के निवासी अली हुसैन और रोइमुन ने प्रधानमंत्री आवास योजना का घर प्राप्त करने के लिए वार्ड सदस्य रुहिना बेग को रिश्वत दी थी। उनका आरोप है, 'सिर्फ हमारे मामले में ही नहीं—काज़ीरबाजार पोलढहर गाँव पंचायत के हर गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना का घर दिलाने के नाम पर हर किसी से 500, 1000, 2000 रुपये लेने कि खबर मिली है। स्थानीय लोगों का दावा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य सरकारी परियोजनाओं में कभी जियो टैगिंग के नाम पर तो कभी किसी अन्य बहाने से सीधे-साधे लोगों को मूर्ख बनाकर पैसा वसूला जा रहा है। काज़ीरबाजार पोलढहर गाँव पंचायत में उजागर इस घटना ने पाथारकांडी के पूरे इलाके में तीव्र हलचल पैदा कर दी है ईस बात कि खबर मिलतेई। इलाकावासियों ने जल्दी से स्पष्ट जांच कर और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।

दिल्ली पुलिस ने साइबर सुरक्षा अभियान के तहत वरिष्ठ नागरिकों को 'डिजिटल अरेस्ट' के बारे में जागरूक किया

● सभी पुलिस स्टेशनों पर हजारों वरिष्ठ नागरिकों ने सत्र में भाग लिया

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली: डिजिटल अरेस्ट के बारे में जागरूकता फैलाने के लगातार प्रयासों को जारी रखते हुए, दिल्ली पुलिस PRO ब्रांच ने IFSO, SPUWAC और दिल्ली के सभी पुलिस जिलों के सहयोग से, आज वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजिटल अरेस्ट के मुद्दे पर एक व्यापक साइबर अपराध जागरूकता सत्र आयोजित किया। यह कार्यक्रम दिल्ली के सभी क्षेत्रीय पुलिस स्टेशनों के साथ-साथ सीनियर सिटीजन्स सेल, SPUWAC यूनिट में एक साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, साइबर सुरक्षा जागरूकता पर एक ज्ञानवर्धक चर्चा सत्र मनोज कुमार, ACP/IFSO और रंजय अत्रिश्या, ACP/APRO द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। सत्र को दिल्ली पुलिस के आधिकारिक YouTube चैनल पर लाइव स्ट्रीम किया गया। सत्र को लाइव देखने की सुविधा के लिए सभी पुलिस स्टेशनों और यूनिट्स में 250 स्क्रीन के साथ विशेष व्यवस्था की गई थी, जहाँ वरिष्ठ नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से कार्यक्रम में शामिल होने और लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया गया था। बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने ऑनलाइन भी सत्र में भाग लिया। सत्र में व्यक्तिगत रूप से शामिल होने वाले वरिष्ठ नागरिकों को डिजिटल अरेस्ट के बारे में जागरूकता पर केंद्रित विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए शैक्षिक पैम्फलेट भी प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम स्थलों पर साइबर सुरक्षा पर स्टैंडी और पोस्टर प्रदर्शित किए गए, और लाइव स्ट्रीम शुरू होने से पहले साइबर सुरक्षा जागरूकता के छोटे वीडियो दिखाए गए।

लाइव स्ट्रीम किए गए संयुक्त चर्चा सत्र के दौरान, वरिष्ठ नागरिकों—जो लक्षित दर्शक थे—जो पुलिस स्टेशनों पर शारीरिक रूप से मौजूद थे और साथ ही जो ऑनलाइन भाग ले रहे थे, उन्हें डिजिटल दुनिया और भौतिक दुनिया के बीच के अंतर के बारे में जागरूक किया गया, और बताया गया कि कैसे साइबर अपराधी समाज के कमजोर वर्गों को निशाना बनाने के लिए इस अंतर का फायदा उठाते हैं। प्रतिभागियों को साइबर अपराधियों द्वारा तथाकथित 'डिजिटल अरेस्ट' के झूठे परिदृश्य बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चालों के बारे में बताया गया। उन्हें प्रवर्तन एजेंसियों के नकली नोटिस के बारे में भी जागरूक किया गया, जिनका इस्तेमाल अपराधी आमतौर पर डराने-धमकाने के लिए करते हैं। वरिष्ठ नागरिकों को सलाह दी गई कि कोई भी संदिग्ध कॉल या संदेश मिलने पर वे शांत रहें, कोई भी व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी साझा करने से बचें, अकेले न रहें बल्कि परिवार के सदस्यों से सलाह लें, संदिग्ध संचार के स्क्रीनशॉट लें या सबूत सुरक्षित रखें, और घटना की सूचना तुरंत उचित अधिकारियों को दें। साइबर अपराधों की रिपोर्ट करने की प्रक्रिया भी विस्तार से समझाई गई।

यह दोहराया गया कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में 'डिजिटल अरेस्ट' जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और पार्टिसिपेंट्स को हमेशा 'रुको, सोचो और काम करो' के सिद्धांत को याद रखने और उसका पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। सेशन को और ज़्यादा दिलचस्प और प्रेरणादायक बनाने के लिए, श्री रंजय अत्रिश्या, ACP/APRO ने सीनियर सिटिज़न्स को मोटिवेट करने और उनका सम्मान करने के लिए अपनी लिखी कविताएँ सुनाईं, जिससे जागरूकता कार्यक्रम में एक पर्सनल टच आया। यह कार्यक्रम दिल्ली पुलिस के कमिश्नर सतीश गोलछा, IPS के नेतृत्व में साइबर अपराधों से लड़ने के लिए दिल्ली पुलिस के लगातार और फोकस्ड प्रयासों का हिस्सा है।? इस कार्यक्रम का मकसद दिल्ली पुलिस के चल रहे ऑनलाइन जागरूकता अभियानों को पूरा करना था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साइबर सुरक्षा के ज़रूरी मैसेज पहुँचाए जा सकें। इसका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा सीनियर सिटिज़न्स तक पहुँचना और उन्हें साइबर अपराधों के बारे में एजुकेट करना भी था, जिसमें डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड के बढ़ते खतरे पर खास ज़ोर दिया गया। हाल के दिनों में, दिल्ली पुलिस द्वारा कई साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इनमें साइबर संवाद के दो एडिशन शामिल हैं, पहले एडिशन में, दिल्ली के अलग-अलग स्कूलों के 350 कंप्यूटर टीचर्स को PHQ में साइबर अपराध के तरीकों और बचाव की रणनीतियों पर ट्रेनिंग दी गई थी, और साइबर संवाद 2.0 के दौरान, 1,000 से ज़्यादा सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लाखों स्टूडेंट्स और टीचर्स ने ऑनलाइन मोड में जागरूकता सेशन में हिस्सा लिया था। इसके अलावा, SPUWAC यूनिट ने सीनियर सिटिज़न्स के लिए एक खास कार्यक्रम आयोजित किया, जहाँ जाने-माने साइबर एक्सपर्ट रक्षित टंडन ने साइबर सुरक्षा पर एक जानकारी भरा लेक्चर दिया।

मां की अस्थियां विसर्जित करने जा रहे चार भाइयों की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

हमीरपुर- मां की अस्थियां लेकर प्रयागराज जा रहे एक ही परिवार के चार भाइयों की बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई। मृतकों में तीन सगे भाई और एक चचेरा भाई शामिल हैं। हादसे में परिवार के तीन अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें कानपुर हायर सेंटर रेफर किया गया है। यह दर्दनाक हादसा हमीरपुर जिले के मौदहा क्षेत्र अंतर्गत इचौली गांव के पास हुआ।

कोहरे में स्लीपर बस ने मारी टक्कर, बोलेरो पूरी तरह पिचकी

महोबा जिले के गयोडी गांव निवासी अनुसुइया (85) की 7 दिसंबर को कैंसर के चलते मौत हो गई थी। अंतिम संस्कार के बाद रविवार सुबह उनके बेटे और रिश्तेदार बोलेरो वाहन से अस्थियां लेकर प्रयागराज के लिए निकले थे। जैसे ही बोलेरो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर इचौली गांव के पास पहुंची, घने कोहरे के कारण पीछे से आ रही तेज रफ्तार स्लीपर बस ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि करीब 14 फीट लंबी बोलेरो सिमटकर मात्र 6 फीट की रह गई।

दरवाजे तोड़कर निकाले गए शव, एक युवक का चेहरा बुरी तरह पिसा

हादसे के बाद बोलेरो सवार सभी सात लोग वाहन में बुरी तरह फंस गए। सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद बोलेरो के दरवाजे तोड़कर शवों और घायलों को बाहर निकाला गया। हादसे में राम सहोदर (45), घनश्याम (58), राधेश्याम (50) – तीनों सगे भाई – और चचेरे भाई सोनू की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सिद्धगोपाल (60), आशाराम (45) और विमल (25) गंभीर रूप से घायल हो गए।

टूरिस्ट बस चालक फरार, गुजरात से चारधाम जा रहे थे यात्री

पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से हालत गंभीर होने पर उन्हें कानपुर रेफर कर दिया गया। क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर एक्सप्रेसवे पर

यातायात बहाल कराया गया। हादसे के बाद टूरिस्ट बस का चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। बस में सवार गुजरात निवासी यात्री भगत भाई ने बताया कि बस में 48 यात्री थे, जो गुजरात से चित्रकूट होते हुए चारधाम यात्रा पर जा रहे थे। सभी यात्री सुरक्षित हैं और उन्हें रेस्ट एरिया में ठहराया गया है।

खेती-किसानी से परिवार चलाते थे मृतक, गांव में पसरा मातम

हादसे में जान गंवाने वाले चारों भाई खेती-किसानी कर अपने परिवारों का पालन-पोषण करते थे। राम सहोदर के दो बेटियां और एक बेटा हैं, पत्नी शांति हैं। सोनू के दो बेटियां और एक बेटा है, पत्नी ममता। घनश्याम के दो बेटे और एक बेटी हैं, पत्नी जय देवी। हादसे की खबर मिलते ही गांव और परिजनों में कोहराम मच गया। मृतकों की पत्नियां और बहन का रो-रोकर बुरा हाल है।